



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 2017/भाद्र 8, 1939

No. 228]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 2017/BHADRA 8, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2017

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्वाय अथवा नॉन-एल्वाय स्टील के कलर कोटेड/प्री पेंटेट फ्लैट उत्पाद" के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच।

एफ. सं. 14/28/2016-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मेसर्स एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मेसर्स जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड इस्पात लिमिटेड, (जिन्हें आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" कहा गया है) ने अधिनियम और पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एल्वाय अथवा नॉन-एल्वाय स्टील के कलर कोटेड/प्री पेंटेट फ्लैट उत्पाद" (जिसे आगे संबद्ध वस्तुएं भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटन-रोधी जांच की शुरुआत करने के साथ-साथ संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के लिए जांच शुरू करने का भी अनुरोध किया है।

- प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 6 (1) के अनुसार संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटन-रोधी जांच शुरू करने के लिए दिनांक 29 जून, 2016 की अधिसूचना जारी की थी, जो कि भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हुई थी, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी।

3. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में दिनांक 20.10.2016 को अधिसूचना संख्या 14/28/2016-डीजीएडी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम द्वारा अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने उपर्युक्त प्राथमिक जांच परिणामों में 30-11-2016 की अधिसूचना सं. 14/28/2016-डीजीएडी द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया था। वित्त मंत्रालय ने सीमा-शुल्क की एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके द्वारा प्राधिकारी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सीमा-शुल्क की दिनांक 11.1.2017 की अधिसूचना संख्या 02/2017-सीमा-शुल्क द्वारा अनन्तिम पाटन-रोधी शुल्क लगाया गया था।

क. क्रिया-विधि

4. इस जांच में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है:-
- (क) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने से पहले भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल और भारत में चीन जन.गण. के दूतावास को आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया है।
- (ख) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को, आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रों के अनुसार संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, और भारत में चीन जन.गण. के दूतावास तथा भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल को तथा अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और उनसे अनुरोध किया था कि वे जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत करा दें।
- (ग) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल और भारत में चीन जन.गण. के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों को अगोपनीय रूपांतरण की प्रति भेजी थी। आवेदन पत्र की एक प्रति जहाँ अनुरोध किया गया था, वहाँ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी दी गई थी।
- (घ) भारत में यूरोपीय संघ के शिष्टमंडल और भारत में चीन जन.गण. के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने उत्तर प्रस्तुत कर दें।
- (ङ) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों से संबद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी थीं:-

यूरोपीय संघ (ईयू)

1. स्टील कोट यूरोप एल्यूम (आर्केलर मित्तल)
2. थेसेनकुर्प स्टील यूरोप एजी
3. टाटा कोरस
4. एस एस ए बी
5. मेटल ट्रेड कोमेक्स
6. वोस्टालपाइन एजी

चीन जन.गण.

1. शंघाई मेटल कॉर्पोरेशन
2. बाओस्टील ग्रुप कॉर्पोरेशन
3. सिनो ईस्टी स्टील एंटरप्राइजेज कं.लि.
4. व्हिंगडाओ सिनो स्टील कं. लि.
5. शंघाई कलर स्टील कं. लि.

- (च) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों/व्यापारियों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-
- (छ) जांच शुरू करने संबंधी अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों/व्यापारियों ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं:-

चीन जन.गण.

1. शांगडोंग हवाफोने स्टील कं. लि. (उत्पादक)
 2. जियांगशू शगांग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. (निर्यातक)
 3. झांगजियागांग शाजिंग हेवेई प्लेट कं. लि. (उत्पादक)
 4. शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा.लि. (निर्यातक)
 5. क्विंगडाओ आरएचटी स्टील कं. लि. (निर्यातक)
 6. मै. जियांगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कं. लि. (उत्पादक/निर्यातक)
- (ज) चीन जनवादी गणराज्य से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का खंडन करते हुए बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण (एमईटी) का दावा नहीं किया है। तथापि, यूक्रेनियाई उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था निरूपण का दावा किया है। इसको प्रकटन विवरण में उपयुक्त स्थान पर ले लिया गया है।
- (झ) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:-
1. सनग्रीन वेंटीलेशन सिस्टम (प्रा.) लि.
 2. श्री रामा स्टील सिंडीकेट,
 3. इंडियन पाइप्स प्रा.लि.
 4. मेटल शाइन रूफिंग,
 5. ब्रिजल एंड संस
 6. कुमार कॉर्पोरेशन
 7. ओरिएंटल मेटल्स इंडिया प्रा.लि.
 8. एम.के.के. मेटल ससेक्शन प्रा. लि.
 9. कुसुम मेटल्स प्रा.लि.
 10. स्टील कं.
 11. शंकर मर्केन्टाइल प्रा.लि.
 12. जी.एम. ट्रेडर्स
 13. पीबी ट्रेडर्स प्रा.लि.
 14. वर्ल्डफूल ऑफ इंडिया लि.
 15. सेमसंग इंडिया इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि.
- (ञ) वर्ल्डफूल ऑफ इंडिया लिमिटेड को छोड़कर जांच की शुरुआत के लिए संबद्ध सामानों के किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं अथवा टिप्पणियां नहीं दी हैं।
- (ट) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पक्षकारों ने जांच के दौरान अनुरोध/टिप्पणियां दायर की हैं:-
1. डेलीगेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन टू इंडिया
 2. वर्ल्डफूल ऑफ इंडिया लि.
 3. जियांगयिन जियांगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स, कं.लि., चीन जन. गण.
 4. चाइना चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स
 5. झांगजियागांग शाजिंग हेवेई प्लेट कं. लि. (उत्पादक)
 6. जियांगशू शगांग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि. (निर्यातक)
 7. शागांग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा.लि. (निर्यातक)

8. शांगडोंग हवाफोने स्टील शीट कं. लि. चीन जन.गण. (उत्पादक)
 9. क्विंगडाओ आरएचटी स्टील कं. लि. (निर्यातक)
- (ठ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाइल के रूप में हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए खुला रख कर उपलब्ध कराया है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को वर्तमान प्रकटन विवरण में शामिल किया गया है।
 - (ड) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी दायर करें।
 - (ढ) जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मंगाई गई थी।
 - (ण) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने मौजूदा जांच की कार्यवाही के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना कर दिया है अथवा ऐसी सूचना अन्यथा प्रदान नहीं की है अथवा जांच में अत्यधिक अडचन डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपना निर्णय रिकार्ड किया है।
 - (त) क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत, निर्माण और बेचने की लागत के आधार पर है निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाता है, तो क्या वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
 - (थ) संबद्ध वस्तुओं को विभिन्न ग्रेडों/आकारों/परिमाण में आयात किया जा रहा है, आवेदकों ने उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है, ताकि पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने के लिए आवेदकों ने उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। तथापि, मामले के वास्तविक सांचे को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने पीसीएन से पीसीएन की तुलना करने की प्रणाली को नहीं अपनाया है।
 - (द) प्राधिकारी द्वारा जितना आवश्यक समझा गया था, आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन किया गया है। जहां कहीं भी लागू होता है, वहां केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर ही उसमें आवश्यक संशोधन सहित विश्वास किया गया है।
 - (ध) यह जांच 1 जुलाई, 2015 से लेकर 31 दिसंबर, 2015 (6 मास) तक की गई थी (जिसे आगे "जांच की अवधि" अथवा "पीओआई" कहा गया है)। क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्तियों की जांच में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 तथा जांच अवधि को भी शामिल किया गया है।
 - (न) याचिकादाताओं ने यह याचिका प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने आईबीआईएस स्रोत से प्राप्त किए गए कारोबार-वार आयात के आंकड़ों पर विश्वास करके संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने का आरोप लगाया है। तथापि, वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि सहित विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकड़े प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त आयातों के कारोबार-वार आंकड़ों पर विश्वास किया है।
 - (न) जांच की कार्यवाही के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों को और प्रदान की गई सूचना को उसके साक्ष्य सहित और वर्तमान जांच में जितना प्रासंगिक पाया गया है, प्राधिकारी द्वारा उस पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।
 - (प) सीमा-शुल्क के आंकड़ों के अनुसार जांच अवधि के लिए विचारित अमरीकी डालर को भारतीय रूपयों में परिवर्तन करने के लिए विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 65.93 रूपए है।
 - (फ) इस अधिसूचना में हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।
 - (ब) प्राधिकारी ने पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने मौखिक विचार व्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करने के लिए 04 मई, 2017 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। इस मौखिक सुनवाई में उपस्थित सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों

को लिखित रूप में 09 मई, 2017 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। पक्षकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे प्रतिवादी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त कर लें और साथ ही उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रत्युत्तर 15 मई, 2017 तक प्रस्तुत कर दें।

- (भ) 12.08.2017 को हितबद्ध पक्षकारों को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया था, जिसमें इस जांच के अनिवार्य तथ्य शामिल थे, जोकि इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनते हैं। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पश्चात अनुरोधों पर विचार किया गया है, जो इस अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना में हद तक सुसंगत पाए गए हैं।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:-

“ क्वायलों में अथवा क्वायलों में नहीं प्री पेंटेड, पेंटेड, कलर कोटेड अथवा ऑर्गेनिक कोटेड फ्लैट स्टील, चाहे वे जिंक, एल्युमीनियम-जिंक अथवा अन्य किसी सबस्ट्रेट कोटिंग के मेटलिक कोटेड सप्ट्रेड सहित हैं अथवा नहीं। ”

ये स्टील या तो अलाय हैं अथवा नॉन अलाय स्टील हैं। चाहे वे क्वायलों अथवा प्लेन शीटों अथवा प्रोफाइल शीटों में प्राइम के हों अथवा गैर-प्राइम हों, जिनमें ट्रेप ज्वायडर, सिनुस्वाइडर, कोरगेटेड अथवा अन्य किसी प्रकार का प्रोफाइल असीमित शामिल हो। ये उत्पाद विभिन्न पेंट गुणवत्ताओं में और कई प्रकार के पेंट रंगों में उपलब्ध हैं भले ही वे प्राइमर अथवा अन्य किसी उपयुक्त सामग्री से कोटेड हों अथवा न हों। इन स्टीलों को स्टील शीट की ऊपरी सतह पर या तो पेंट किया जाता है अथवा निचली सतह पर पेंट किया जाता है अथवा शीट्स और नीचे की सतहों, दोनों पर पेंट किया जाता है। इस उत्पाद की आपूर्ति गार्ड फिल्म/लेमिनेशन के साथ अथवा उसके बिना की जा सकती है।

6. विचाराधीन उत्पाद बेरियर संरक्षण के साथ क्षरण की प्रतिरोधकता देता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में किया जाता है, जिनमें निर्माण, छत बनाना, दीवार बनाना, पैनल बनाना, क्लेडिंग और बेकिंग, आटोमोटिव, सफेद सामान और उपकरण तथा फर्नीचर आदि शामिल हैं।
7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रशुल्क मद 72107000, 72124000, 72259900 और 72269990 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, आयात कुछ अन्य आईटीसी एचएस कोडों में भी पाए गए हैं यथा 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72103010, 72103090, 72104100, 72104900, 72105000, 72106100, 72106900, 72109010, 72109090, 72121010, 72121090, 72122090, 72123090, 72125020, 72125090, 72126000, 72255030, 72259200 और 72261100. सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

ख 1. हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों पर निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

(क) एक निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वे भारत को 6 एमएम अथवा उससे अधिक की मोटाई वाला बीच की अथवा भारी प्लेट कर निर्यात करते हैं जो एक शॉप प्राइमर किस्म से पेंट किया जाता है। यह उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं है परंतु फिर भी उन्होंने पूरी सावधानी के एक उपाय के रूप में निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं। विचाराधीन उत्पाद तथा निर्यातक द्वारा निर्यातित उत्पाद के अनुप्रयोगों के बीच अंतर है। सामान्य रूप में विचाराधीन उत्पाद की मोटाई 6 एमएम से कम है।

(ख) झांगजियागंग शाजिंग हैवी प्लेट कंपनी लिमिटेड ने “प्राइम कोटेड हॉट रोलड नान एलाय स्टील प्लेट्स” के लिए उसे अलग रखने की मांग की है। झांगजियागंग ने अपने उत्पाद को हटाने के लिए निम्नलिखित कारण दिए हैं :

- (1) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आईएस 14246-2013 है जबकि झांगजियागंग का उत्पाद बी एस ई एन 10025-3:2004 है।।
- (2) भिन्न रासायनिक एवं भौतिक विशेषताएं।
- (3) स्टील ग्रेड भिन्न है।
- (4) उत्पाद प्रक्रिया भिन्न है। कोटिंग की कम से कम दो परतें होनी चाहिए और सेका जाना चाहिए

परंतु झांगजियागंग द्वारा निर्यातित उत्पाद के लिए अतिरिक्त उत्पादन प्रक्रिया केवल ब्लास्ट क्लीनिंग तथा पेंट स्प्रेइंग है।

(5) झांगजियागंग द्वारा निर्यातित उत्पाद की बिक्री कीमत भिन्न है।

ख 2. घरेलू उद्योग के विचार

9. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में सभी कोटेड उत्पाद शामिल हैं चाहे वे प्रीपैटेड हों, पेटेड हों, कलर कोटेड हों अथवा कॉयलस में आर्गेनिक कोटेड फ्लैट स्टील हों, चाहे वे जिंक, एल्युमिनियम-जिंक अथवा अन्य किसी सप्रेट कोटिंग के मैटलिक हों अथवा मैटलिक कोटेड सप्रेट न हों। ये स्टील या तो एलाय के हैं अथवा नॉन अलाय स्टील के हैं। भले ही वे प्राइम क्वालिटी के हों अथवा गैर-प्राइम क्वालिटी के हों, चाहे वे क्वायलों के रूप में हों अथवा प्लेन शीट के रूप में हों अथवा प्रोफाइल शीट के रूप में हों जिनमें ट्रेपजवाइडल सिनुसोइडल कोरूगेटेड अथवा अन्य किसी किस्म के प्रोफाइल तक सीमित न होकर शामिल हों।
- (ख) निर्यातकों के इस अनुरोध के संबंध में 6 एमएम अथवा उससे अधिक की मोटाई की भारी प्लेटों को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाए, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि ये प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर पहले से ही शामिल नहीं हैं।
- (ग) घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्राधिकारी ने अपने प्राथमिक जांच परिणामों में पहले ही माना है कि 6 एमएम अथवा उससे अधिक की मोटाई की प्लेटें उत्पाद क्षेत्र के भाग का रूप नहीं हैं। अतः झांगजियागंग द्वारा किया गया उत्पाद को हटाने का अनुरोध किसी औचित्य से हीन है और इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- (घ) यहां तक कि अन्यथा भी कोई कानूनी तर्क में औचित्य नहीं है जिसके आधार पर झांगजियागंग द्वारा उसे हटाए जाने का अनुरोध किया गया है।
- (ङ) विचाराधीन उत्पाद में प्राइमर कोटेड नॉन एलाय स्टील शीट है। यह तथ्य कि झांगजियागंग द्वारा निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए अन्य निर्यातित उत्पादों के मानकों की तुलना में विभिन्न उत्पाद मानकों का अनुसरण करता है, हटाए जाने का कोई आधार नहीं बन सकता। इसी प्रकार, अन्य निर्यातित उत्पाद जो विचाराधीन उत्पाद का भाग है, से निर्यातित उत्पाद के ग्रेड, भौतिक विशेषताओं, उत्पादन प्रक्रिया और बिक्री कीमत में अंतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटाए जाने का आधार नहीं हो सकता।
- (च) झांगजियागंग ने विचाराधीन उत्पाद अर्थात् आयातित उत्पाद जोकि जांचाधीन है, की अन्य किस्मों से कुछ मानदंडों के आधार पर अपनी उत्पाद किस्म को भिन्न करने का प्रयास किया है। तथापि, कम से कम विचाराधीन उत्पाद को हटाए जाने की मांग करने वाले निर्यातक को अपने उत्पाद को भारत में समान घरेलू उत्पाद से पहचान करना तथा उससे अलग करना है। झांगजियागंग इस प्रकार के अंतरों का दावा भी नहीं करता है। झांगजियागंग का यह भी दावा नहीं है कि उसका उत्पाद प्रतिस्थापनीय नहीं है और समान घरेलू उत्पाद के साथ सीधे ही प्रतिस्पर्धी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि घरेलू उद्योग समान उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता जो उनके द्वारा निर्यातित उत्पाद के सभी मामलों में अथवा परिभाषा की दूसरी स्थिति में अथवा बारीकी से मिलती हुई विशेषताओं वाले उत्पाद के संबंध में समान हैं। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इस उत्पाद को हटाना तर्कसंगत नहीं है।

ख 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों पर हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका निदान किया गया है, जो कि निम्नानुसार हैं:-

- (क) घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद में स्टील शामिल हैं चाहे वे एलाय हों अथवा नॉन अलाय स्टील हों। भले ही वे प्राइम क्वालिटी के हों अथवा गैर-प्राइम क्वालिटी के हों, चाहे वे क्वायलों के रूप में हों अथवा प्लेन शीट के रूप में हों अथवा प्रोफाइल शीट के रूप में हों जिनमें ट्रेपजवाइडल सिनुसोइडल कोरूगेटेड अथवा अन्य किसी किस्म के प्रोफाइल तक सीमित न होकर शामिल हों। तदनुसार, विचाराधीन उत्पाद 6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई की प्लेटें शामिल नहीं करता।
- (ख) प्राधिकारी ने झांगजियागंग द्वारा हटाए जाने के अनुरोध की जांच की है और वे नोट करते हैं कि 6 एमएम तथा उससे अधिक की मोटाई की प्लेटों को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग कर दिया गया है अतः उनकी चिंता का पहले ही समाधान कर दिया गया है।

(ग) समान वस्तु के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं।"। रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है तथा दोनों ही उत्पाद वास्तविक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसे मानदण्डों के संदर्भ में तुलनीय है। याचिकादाताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई विशेष अंतर नहीं है तथा दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है। उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर रहे हैं। प्राधिकारी का मानना है कि आवेदकों द्वारा विनिर्मित उत्पाद, संबद्ध देश से भारत में आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु हैं।

11. तदनुसार, इस जांच में विचाराधीन उत्पाद "क्वायलों में अथवा क्वायलों में नहीं प्री पेंटेड, पेंटेड, कलर कोटेड अथवा ऑर्गेनिक कोटेड फ्लैट स्टील, चाहे वे जिंक, एल्युमीनियम-जिंक अथवा अन्य किसी सबट्रेट कोटिंग के मेटलिक कोटेड सप्ट्रेड सहित हैं अथवा नहीं, जिनमें 6 एमएम अथवा उससे अधिक मोटाई की प्लेटें शामिल नहीं हैं," है।

ग. गोपनीयता

ग 1. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

12. अत्यधिक गोपनीयता के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नानुसार हैं:-

- (क) यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का सहारा लिया है जिसमें उन्होंने हितबद्ध पक्षकारों को सार्थक टिप्पणियां देने से वंचित किया है जोकि पाटनरोधी नियमावली में दिए गए गोपनीयता के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है।
- (ख) आवेदक उद्योग ने कार्यशील पूंजी के परिकलन, आवधिक ऋण पर ब्याज, मूल्यहास, विविध आय, क्रय और बिक्री नीति, मालसूची का मूल्यांकन, गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया आदि जैसा कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रदान किए बिना पर्याप्त सूचना को गोपनीय रखा है। यह नियमानुसार अनुमति योग्य नहीं है, जैसाकि ऊपर प्रावधानों से देखा जा सकता है।
- (ग) याचिकाकर्ता कुछ संगत आर्थिक कारकों तथा नियमावली के नियम 11 में सूचीबद्ध तत्वों एवं उसके अनुबंध-2 के पैरा 4 में उल्लिखित कारकों का मूल्यांकन करने में विफल रहा। यूनिट कीमत संबंधी सूचीबद्ध आंकड़े, कुल लागत, निवेश, रोजगार और स्टॉक स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं और याचिका के विवरणात्मक रूपांतर में उनका विश्लेषण नहीं किया गया है जोकि सार्थक विश्लेषण का अभाव दर्शाता है।

ग 2. घरेलू उद्योग के विचार

13. अतिरिक्त गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- (क) हितबद्ध पक्षकारों ने कार्यशील पूंजी, आवधिक ऋण पर ब्याज, देय तथा चक्रवृद्धि ब्याज, मूल्यहास की दर, घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित आय, लागत का विवरण, क्रय और बिक्री नीति आदि के संबंध में गोपनीयता प्रदान किए जाने का विरोध किया है। उपर्युक्त सभी सूचनाएं प्रकृति में अत्यधिक व्यापार संवेदनशील हैं और ऐसी सूचना को प्रकट करने से घरेलू उद्योग का पूर्वाग्रह बनेगा। साथ ही, एक परिपाटी के रूप में उपर्युक्त कोई भी सूचना प्राधिकारी द्वारा किसी भी पाटनरोधी जांच में प्रकट नहीं की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह सूचना अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- (ख) हितबद्ध पक्षकारों ने केवल यह आरोप लगाया है कि वे याचिका में लागत संबंधी सूचना के संबंध में दावा किए गए गोपनीयता के कारण घरेलू उद्योग द्वारा रखे गए दावों को पूरी तरह से समझने में समर्थ नहीं हैं। इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना प्रकृति में व्यापार संवेदनशील है और उसे प्रकट नहीं किया जा सकता, हितबद्ध पक्षकार विशिष्ट दावे का एक भी उदाहरण देने में भी विफल रहे, जिसे वे गोपनीय मानी जाने वाली सूचना के उपलब्ध न होने के कारण उत्तर नहीं दे पाए। इस प्रकार, उन हितबद्ध पक्षकारों के दावे में कोई औचित्य नहीं है जिन्होंने केवल उस सूचना की सूची दी है, जिसकी गोपनीयता का दावा उस गोपनीय सूचना के उपलब्ध न होने के कारण उन्हें पूर्वाग्रह होने का उल्लेख किए बिना दावा किया गया है।

ग 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

14. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

15. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की गई है और उनका तदनुसार निदान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जो भी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है उसे गोपनीय नहीं माना जा सकता।

घ. घरेलू उद्योग और उसका आधार

16. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

17. यह आवेदन पत्र मै0 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने दायर किया है। इन उपर्युक्त उत्पादकों का उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात है और भारतीय उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है।

घ 1. घरेलू उद्योग के आधार के बारे में निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. भारतीय उत्पादकों द्वारा याचिका में समर्थन का परिकलन तथा आधार स्पष्ट नहीं है और इन परिकलनों के लिए जिस दस्तावेज पर विश्वास किया गया है, उसे हितबद्ध पक्षकारों को दिया जाना चाहिए।

घ 2. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. इस मुद्दे के संबंध में कि याचिका के समर्थन के परिकलन और आधार स्पष्ट नहीं हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन पत्र मै0 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जे एस डब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा दायर किए गए हैं और इन उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में भारी अनुपात है। इन उत्पादकों का हिस्सा भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है जैसाकि निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आवेदन पत्र में कोई समर्थन नहीं है।

उत्पादन	इकाई	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 15- दिसंबर 15 (क)	पीओआई (जुलाई 15- दिसं 15)	पीओआई (ए)
याचिकाकर्ता							
-एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड.	मी.ट.	***	***	***	***	***	***
-जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्राडक्ट्स लिमिटेड	मी.ट.	***	***	***	***	***	***
याचिकाकर्ता का कुल उत्पादन	मी.ट.	414,910	576,975	559,218	591,385	277,318	554,636
अन्य उत्पादक	मी.ट.	407,090	303,025	348,782	320,615	160,682	321,364
कुल घरेलू उत्पादन (जेपीसी आंकड़ों के आधार पर)	मी.ट.	822,000	880,000	908,000	912,000	438,000	876,000

20. इसलिए प्राधिकारी का यह मानना है कि आवेदकों का भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख भाग बनता है और जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक पाटन-रोधी निमयावली के नियम 2 (ख) में उल्लिखित घरेलू उद्योग के आधार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और घरेलू उद्योग बनते हैं।

ड. न्यूनतम सीमाएं

21. वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से प्राप्त हुए आयात के आंकड़ों और संबद्ध देश से सहयोगी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों को न्यूनतम स्तर से अधिक पाया गया है।

च. विविध मुद्दे

22. वर्तमान जांच के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनेक मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें पाटन का निर्धारण करने की कार्यप्रणाली और घरेलू उद्योग की क्षति के दावे शामिल हैं। जबकि पाटन और क्षति का निर्धारण करने से संबंधित मुद्दों का निदान इस प्रकटन विवरण में उपयुक्त स्थानों पर कर दिया गया है, पक्षकारों द्वारा जांच के बारे में उठाए गए सामान्य मुद्दों की जांच यहां की गई है। संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

च.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विविध मुद्दे

- (क) जांच की अवधि "प्रतिनिधिकारक तथा यथासंभव हाल की" होनी चाहिए। एक वर्ष की जांच की अवधि निर्धारित करने से विचलन याचिकाकर्ता द्वारा तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सकारात्मक साक्ष्य से सिद्ध किया जाना चाहिए जो इस मामले में मौजूद नहीं है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 6 माह की जांच की अवधि बहुत कम है और वह कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए।
- (ख) याचिका में प्रस्तुत की गई सूचना जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है और कुछ आंकड़े गलत ढंग से गोपनीय माने गए हैं। गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया है।
- (ग) घरेलू उद्योग को डब्ल्यू टी ओ करारों के उल्लंघन में बहुविध संरक्षण पहले ही प्राप्त हुए हैं:
- सीमाशुल्क की वृद्धि
 - न्यूनतम आयात कीमत
 - अन्य स्टील उत्पादों के संबंध में पाटनरोधी जांच
- (घ) आयात आंकड़े हितबद्ध पक्षकारों को एम एस एक्सल फॉर्मेट में दिए जाने चाहिए।
- (ङ) एनआईपी की गणना के लिए 22 प्रतिशत का आरओसीई बहुत अधिक है। बृज स्टोन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट के निर्णय पर विश्वास किया गया है।

- (च) संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ मिलेगा और भारतीय उद्योग के व्यापक हित में नहीं होगा।

च 2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) अधिनियम की धारा 9क(3) उत्पाद के पाटन के इतिहास के संदर्भ में है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे संबद्ध सामानों पर पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभावी तौर पर लगाने की सिफारिश करें क्योंकि पाटनरोधी शुल्क पूर्व प्रभाव से लगाए जाने के लिए शर्तें पूरी हैं।
- (ख) संबद्ध सामानों के पाटन के साक्ष्य हैं जोकि इस तथ्य से सिद्ध है कि कई देशों ने संबद्ध सामानों के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच शुरू की है। भारत में विचाराधीन उत्पाद का भारी पाटन बहुत ही कम समय में हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- (ग) कुछ हितबद्ध पक्षकारों का विचार है कि क्षति रहित कीमत का परिकलन करने में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ यथोचित नहीं है। घरेलू उद्योग उपरोक्त तर्क का सुदृढता से खंडन करता है और उसका निवेदन है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ क्यों यथोचित नहीं है। वास्तव में सेस्टेट ने हाल ही के दो निर्णयों में यह पाया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी की सुसंगत पद्धति के अनुसार नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ वैध है और इसका खंडन करने वाले पक्षकार का यह दायित्व है कि वह ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे कि नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ क्यों यथोचित नहीं है। इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान सेस्टेट के मेरिनो पेनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिनांक 27 नवंबर, 2015 के अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53541/2015-सीयू (डीबी) और एक्सिस कोर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिनांक 12 सितंबर, 2016 के अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53462/2016-सीयू (डीबी) की ओर आकर्षित किया जाता है। सेस्टेट के उपरोक्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले में नियोजित पूंजी पर 22% प्रतिलाभ वैध है और इसकी संपुष्टि अंतिम जांच परिणाम में भी सुनिश्चित रूप से की जानी चाहिए।
- (घ) निर्यातक अच्छी तरह जानते हैं कि वे पाटन का सहारा ले रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें काफी कम हुई हैं, जोकि संबंधित देशों के लिए पहुंच मूल्य से सिद्ध है।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

23. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच की गई और इनका निम्नलिखित रूप में समाधान किया गया :

- (क) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि जांच की अवधि 6 माह से अधिक होनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी परिपाटियों संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार (डब्ल्यू टी ओ दस्तावेज संख्या जी/एडीपी/6 दिनांक 16 मई, 2000):

“.... पाटन संबंधी जांच के लिए आंकड़ा एकत्र करने की अवधि सामान्यतः 12 माह होनी चाहिए और किसी भी दशा में 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए जोकि जांच की शुरुआत की तारीख के निकट हो, जैसाकि व्यवहारिक हो।”

अतः उपर्युक्त सिफारिश के मद्देनजर, 6 माह की अवधि जांच की अवधि के रूप में ली जा सकती है। प्राधिकारी ने विगत में भी अन्य जांचों में जांच की अवधि 6 माह दी है।

- (ख) इस मुद्दे के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने डब्ल्यूटीओ करारों के उल्लंघन में बहुविध संरक्षण पहले ही प्राप्त किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसे पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित स्थिति की ही जांच करनी होती है। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क में वृद्धि करके डब्ल्यू टी ओ करारों का कोई उल्लंघन नहीं है। अन्य स्टील उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क लागू होने का यह अभिप्राय नहीं है कि घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति नहीं हो रही है।
- (ग) भारत सरकार द्वारा एमआईपी एक अस्थायी उपाय के रूप में शुरू किया गया था और वह 3 दिसंबर, 2016 तक लागू था।
- (घ) इस मुद्दे के संबंध में कि आयात आंकड़े एम एस एक्सल फार्मेट में दिए जाने चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे विशेष अनुरोध पर दावेदारों को दे सकते हैं बशर्ते कि वे एक वचनबद्धता दें कि वे केवल इस जांच के प्रयोजन के लिए ही उन आंकड़ों का प्रयोग करेंगे।

- (ड) प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह तर्क कि संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ होगा, यह अभी नहीं माना जा सकता। पाटनरोधी जांचें पाटन की मात्रा का मूल्यांकन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए तथ्यों और कानून के आधार पर हैं तथा परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षतिकारक प्रभाव के आधार पर हैं तथा यह घरेलू उद्योग को व्यापार का समान एवं स्वच्छ स्तर प्रदान करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त पाटनरोधी उपाय लगाने की सिफारिश करने के लिए है।
- (च) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जांच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया है।
- (छ) पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटन-रोधी शुल्क लागू करने के अनुरोध के संबंध में सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क (3) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:-

यदि सरकार का ऐसी पाटित वस्तु के संबंध में जिसके कारण क्षति हो रही है, यह विचार है कि -

- ऐसे पाटन का इतिहास रहा है जिसके कारण क्षति हुई है अथवा आयातक इस तथ्य से अवगत था अथवा अवगत होना चाहिए था कि निर्यातक पाटन करने की प्रक्रियाएं अपना रहा है और ऐसे पाटन के कारण क्षति होगी और*
- अपेक्षाकृत अल्प समय में आयातित ऐसी वस्तु के व्यापक पाटन होने के कारण क्षति हो रही है, जो कि समय और पाटित आयातित वस्तु की मात्रा तथा अन्य परिस्थितियों के आलोक में लागू किए जाने वाले पाटन-रोधी शुल्क के उपचारी प्रभाव को गंभीर रूप से कम करेगी, तो -*

केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उप-धारा (2) के अंतर्गत लागू किए जाने वाले पाटन-रोधी शुल्क को लागू किए जाने की तारीख से पूर्व तारीख से पाटन-रोधी शुल्क लागू कर सकती है, लेकिन उप-धारा के अंतर्गत ऐसी अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिनों के बाद नहीं और उस समय लागू किसी विधि में निहित कोई भी प्रावधान होने के बावजूद ऐसा शुल्क ऐसी दर से और ऐसी तारीख से लागू होगा, जो कि अधिसूचना में विनिश्चित होगा।

- (ज) मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी इस मामले में पूर्वव्यापी प्रभाव से पाटन-रोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करना उचित नहीं समझते हैं।
- (झ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि क्षतिरहित कीमत का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए लगाई गई पूंजी पर आय 22 प्रतिशत से कम क्यों होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, 22 प्रतिशत के रूप में आर ओ सी ई लेना प्राधिकारी की मानक परिपाटी है।
- (ञ) वर्तमान जांच की शुरुआत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/आंकड़ों का प्रथम दृष्टया विश्लेषण करने के आधार पर की गई है, जिससे ऐसा पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन के कारण आवेदकों को क्षति हो रही है और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध है। प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए भ्रामक आंकड़ों और प्राधिकारी द्वारा आंकड़ों का अनुचित मूल्यांकन किए जाने के कारण जांच की शुरुआत करना कानूनी रूप से निकृष्ट है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू करने के समय याचिकादाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर सूचना की परिशुद्धता और पर्याप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया वे स्वयं संतुष्ट हुए हैं।

बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एम ई टी) सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

सामान्य मूल्य

24. सामान्य मूल्य के संबंध में धारा 9 क (1) (ग) के अंतर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

- (1) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (2) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री

मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री औष्र सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत :

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।”

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के संबंध में प्रावधान

25. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

8 (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश" शब्द का अर्थ ऐसा कोई देश है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी ने लागत या कीमत निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर प्रचालन करते हुए निर्धारित नहीं किया है क्योंकि ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियां उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार पण्य वस्तुओं का उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करती हैं।

(2) ऐसी एक परिकल्पना होगी कि कोई देश जिसे जांच से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा या विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में निर्धारित किया गया है या माना गया है, को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाएगा;

बशर्ते कि तथापि यह कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ऐसे देश की संबंधित फर्मों निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस आशय की सूचना और साक्ष्य उपलब्ध कराके ऐसी किसी परिकल्पना का खंडन कर सकते हैं जो यह सिद्ध करती हो कि वह देश उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंडों के आधार पर एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेंगे कि क्या :-

- (क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे-खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन है;
- (ग) इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और

(घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है।

बशर्ते कि फिर भी जहां इस पैरा में विनिश्चित मानदंड के आधार पर लिखित साक्ष्य द्वारा ऐसा दर्शाया गया है कि एक अथवा अधिक ऐसी फर्मों के लिए पाटन-रोधी जांच के अध्यक्षीन बाजार की दशाएं विद्यमान हैं, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पैराग्राफ 7 और इस पैराग्राफ में उल्लिखित सिद्धांतों के बजाए पैराग्राफ 1 से 6 में उल्लिखित सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं।

निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन:

26. एम.ई.टी. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए एवं प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझे गए विभिन्न निवेदनों की जांच की जाती है और निम्नानुसार समाधान किया जाता है:-

- (क) चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय चीन के उत्पादकों के विक्रय मूल्य और लागत के बारे में विचार करना चाहिए क्योंकि चीन जनवादी गणराज्य डब्ल्यूटीओ के अपने स्वीकृति प्रोटोकॉल के अनुसार वर्ष 2016 में बाजार अर्थव्यवस्था में पहुंचा है।
- (ख) सामान्य मूल्य का निर्धारण उपयुक्त नहीं है। सामान्य मूल्य का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त उत्पादन लागत कम क्षमता उपयोग के कारण बहुत अधिक है।
- (ग) घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण का पर्याप्त साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं है। इसके अतिरिक्त, निर्मित सामान्य मूल्य के आधार पर औसत पाटन परिकलन अत्यधिक साधारण है और वह विभिन्न प्रकार के उत्पादों को नहीं दर्शाता है।
- (घ) पाटन एवं क्षति संबंधी परिकलनों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों तथा गुणवत्ताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए निवेदन:-

27. एम.ई.टी., सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए एवं प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए विभिन्न सामान्य निवेदन निम्नानुसार हैं:-

- (क) हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किया गया यह दावा गलत है कि ई.सी. फॉसनर में अपीलीय निकाय ने स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था स्तर प्राप्त करने हेतु चीन के लिए सशक्त औचित्य उपलब्ध कराया है। अपीलीय निकाय रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है। अपीलीय निकाय रिपोर्ट को 28 जुलाई, 2011 को, अर्थात् 11 दिसंबर 2016 की समाप्ति तारीख से 5 वर्ष पहले डब्ल्यू टी ओ डी एस बी के द्वारा स्वीकार किया गया था। ई.यू. फॉसनर में, चीन जनवादी गणराज्य मूल के कुछ लौह अथवा इस्पात के फॉसनरों के आयातों पर ई.सी. के द्वारा निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने को डब्ल्यूटीओडीएसबी से पूर्व चुनौती दी जा रही थी। स्पष्टतः एक बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में चीन की स्थिति से संबंधित मुद्दा डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के समक्ष नहीं था।
- (ख) चीन का स्वीकृति प्रोटोकॉल में यह प्रावधान नहीं है कि चीन को 15 वर्षों के बाद स्वतः ही बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर मिल जाएगा। इसमें केवल यह कहा है कि पैरा 15 (क) (ii) के बहुत विशिष्ट प्रावधान लागू होने समाप्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 15 के अन्य भाग (अनुच्छेद 15 (क) (i) सहित) लागू रहेंगे। अनुच्छेद 15 (क) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य जांच के अधीन उद्योग के लिए या तो चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो घरेलू कीमतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो। अनुच्छेद 15 (क) (i) में यह भी प्रावधान है कि चीन की कीमतों अथवा लागतों का उस स्थिति में उपयोग किया जाएगा यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध कर सकता है कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ प्रचलन में हैं।
- (ग) पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 8 (4), अनुबंध-I में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे देश को बाजार अर्थ-व्यवस्था देश के रूप में मान सकता है, जिसको डब्ल्यू टी ओ सदस्य देश के द्वारा पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनार्थ मानदण्ड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था देश के रूप में माना गया है। चीन जनवादी गणराज्य के लिए इस मानदण्ड को पूरा करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया है।
- (घ) वर्तमान जांच की शुरुआत करने की तारीख 2 जून, 2016 थी। चीन जनवादी गणराज्य के स्वीकृति प्रोटोकॉल में अपेक्षित समाप्ति तारीख 11 दिसंबर, 2016 है। चाहे प्रावधान की समाप्ति को हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा कथित रूप से प्रभावी बताया गया है, परन्तु इसे जांच के लिए लागू करने की भांति पूर्व-व्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है, जो 11 दिसंबर, 2016 से पूर्व शुरू की गई थी।
- (ङ) चीन का कोई भी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था स्तर को पूरा नहीं कर सकता है।

- (च) जब तक प्रतिक्रिया देने वाले चीन के निर्यातक नियमावली के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करना अपेक्षित होता है।
- (छ) चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है।
28. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध करते हुए विस्तृत अनुरोध किए हैं कि जिन उत्पादकों/निर्यातकों को असहयोगी माना गया है, उन्हें अंतिम जांच परिणाम में भी असहयोगी माना जाता रहना चाहिए।

प्राधिकारी द्वारा जांच

चीन के उत्पादों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दावे:-

29. चीन के स्वीकृति प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ट) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

30. अनुच्छेद 15 में यह अपेक्षा होती है कि उप-पैराग्राफों में से एक पैराग्राफ के प्रावधान चीन की स्वीकृति की तारीख से 15 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इस उप-पैराग्राफ के प्रावधान 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गए। चूंकि घरेलू उपयोग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन के तथ्य जांच अवधि के आधार पर सुनिश्चित हुए हैं, इसलिए केवल जांच अवधि के दौरान ही प्रचालित परिस्थितियां वर्तमान जांच हेतु प्रासंगिक उपयुक्त और जरूरी हैं। वर्तमान समीक्षा के लिए जांच की अवधि (पी.ओ.आई.) जुलाई, 2015 से दिसंबर, 2015 है। चूंकि अनुच्छेद 15 का उप-पैराग्राफ जांच की अवधि के दौरान अस्तित्व में था, इसलिए प्राधिकारी उस स्थिति में उस पद्धति का उपयोग करने के लिए पात्र है, जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित है, यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि उस उत्पाद के विनिर्माण उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का विनिर्माण करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी परिस्थियाँ प्रचलित हैं।
31. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत 3 वर्षों में चीन जनवादी गणराज्य को भारत और अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों के द्वारा पाटनरोधी जांचों में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। नियमावली के तहत निर्यातक देश अथवा व्यक्तिगत निर्यातकों के द्वारा अनुमान का खण्डन करने के अध्यक्षीन चीन जनवादी गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है।
32. यथा संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1, पैराग्राफ 8 के अनुसार यदि चीन जनवादी गणराज्य का निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के आधार पर सूचना और पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराता (कराते) हैं तो गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का खण्डन किया जा सकता है। बाजार अर्थव्यवस्था ट्रीटमेंट प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/ पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए अपेक्षित है, ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मानदण्ड के बारे में यह विचार कर सके कि क्या:-
- (क) कच्चे माल, प्रौद्योगिकी और श्रम, उत्पादन बिक्री और निवेश की लागत सहित कीमतों, लागतों एवं निवेशों के बारे में ऐसे देशों में संबंधित फर्मों के निर्णय आपूर्ति और मांग को दर्शाते हुए बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में तथा इस संबंध में राज्य के सार्थक हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं और क्या बृहद निवेशों की लागतें बाजार मूल्यों का काफी प्रतिबिम्बित करती है।
- (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतें और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से, विशेषकर परिसम्पत्तियों के मूल्य-हास, अन्य बट्टे-खाते डालने, विनिमय व्यापार एवं ऋणों की क्षतिपूर्ति करके भुगतान के संबंध में काफी विकृतियों के अध्यक्षीन होती है।
- (ग) ऐसी फर्मों द्वारा विवाल्यापन एवं सम्पत्ति संबंधी कानूनों के अध्यक्षीन होती हैं जो फर्मों के प्रचालनों के लिए कानूनी विश्वसनीयता एवं स्थिरता के बारे में गारंटी देता है; और
- (घ) विनिमय दर बाजार दर पर परिवर्तित की जाती है।
33. यह नोट किया है कि चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थ-व्यवस्था ट्रीटमेंट का दावा नहीं किया है। तदनुसार प्राधिकारी को चीनी उत्पादकों के लिए तथा वे मानते हैं कि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक बाजार अर्थ-व्यवस्था परिस्थितियों के तहत कार्य नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार सामान्य मूल्य पर निर्धारण के लिए निर्मित सामान्य मूल्य को लिया है।

सामान्य मूल्य का निर्धारण

34. प्राधिकारी ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह देते हुए उन्हें प्रश्नावलियां भेजी। निम्नलिखित पक्षकारों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं :
1. शानडोंग हवाफोन स्टील कंपनी लिमिटेड चीन. जन.गण. (उत्पादक)
 2. जियांगशू शांगंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड . चीन. जन.गण. (निर्यातक)
 3. झांगजियांगंग साजिंग हेवी प्लेट कं. लि., चीन जन.गण. (उत्पादक)
 4. शांगंग इंटरनेशनल सिंगापुर प्रा.लि. चीन जन.गण.(निर्यातक)
 5. क्विंगडाओ आरएचटी स्टील कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण.(निर्यातक)
 6. जियांगजिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वक्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण (उत्पादक/निर्यातक)

चीन जन.गण. में, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

35. यह नोट किया जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है। अतः प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निर्मित सामान्य मूल्य अपनाया है।
36. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण प्राधिकारी के द्वारा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार, चीन जनवादी गणराज्य में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में घरेलू विक्रय मूल्य अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित किसी अन्य देश के लिए ऐसे किसी तीसरे देश से निर्यात कीमतों के आधार पर करना होता है। तथापि, यदि सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर बताए विकल्पों के आधार पर नहीं किया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजि समान उत्पाद हेतु भारत में वास्तव में भुगतान किए गए अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण कर सकता है।
37. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं की किसी विश्वसनीय कीमत और लागत संबंधी ब्यौरों के न होने की स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किए अथवा देय कीमत के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/ सभी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और इसे पाटन मार्जिन सारणी में नीचे दर्शाया गया है।

यूरोपीय संघ में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और वर्तमान जांच में प्राधिकारी का सहयोग नहीं किया है। यूरोपीय संघ में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध सामानों के लिए कारखानागत स्तर पर भारित औसत सामान्य मूल्य निर्धारित किया है और उसे पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दर्शाया गया है।

निर्यात कीमत

मै. जियांगशू शांगंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड . चीन. जन.गण. और शांगंग इंटरनेशनल (सिंगापुर) प्रा.लि. सिंगापुर., संबंधित व्यापारियों के माध्यम से मै. झांगजियांगंग साजिंग हेवी प्लेट कं. लि., चीन जन.गण. (उत्पादक),

39. मै. झांगजियांगंग साजिंग हेवी प्लेट कं. लि., चीन जन.गण. ("शाजिंग") द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि शाजिंग संबद्ध सामानों का उत्पादक है। इसकी संबंधित कंपनी मै. जियांगशू शांगंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड(शांगंग इंटरनेशनल) ने मै. शांगंग इंटरनेशनल (सिंगापुर) प्रा.लि. (शांगंग एसजी) दूसरी संबंधित व्यापारिक कंपनी के माध्यम से भारत में संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।
40. शांगंग एस जी द्वारा प्रस्तुत उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि शांगंग एस जी ने आगे संबद्ध सामानों को सेमसंग सी तथा टी कॉर्पोरेशन कोरिया (सेमसंग) को बेचा। सेमसंग ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, शाजिंग ने परिशिष्ट-2 में भारत को कोई निर्यात होना सूचित नहीं किया है। उत्पादक से परिशिष्ट-2 में सूचना के अभाव में भारत को कारखानागत निर्यात कीमत सुनिश्चित करना संभव नहीं है।
41. अतः सेमसंग द्वारा असहयोग सहित शाजिंग से पूर्ण सूचना के अभाव के मद्देनजर प्राधिकारी शाजिंग द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार नहीं करते। तदनुसार, शाजिंग के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर है।

असंबद्ध व्यापारी मै. क्विंगडाओ आरएचटी स्टील कंपनी लिमिटेड के माध्यम से शानडोंग हवाफोन स्टील शीट कंपनी लिमिटेड (उत्पादक)

42. मै. शानडोंग हवाफोन स्टील शीट कंपनी लिमिटेड चीन जन गण (हवाफोन) द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि हवाफोन संबद्ध सामानों का उत्पादक है और उसने संबद्ध सामानों का निर्यात असंबद्ध व्यापारी मै. क्विंगडाओ आरएचटी स्टील कंपनी लिमिटेड (आरएचटी) के माध्यम से किया है। हवाफोन ने उसके द्वारा दायर परिशिष्टों में घरेलू बिक्री के रूप में सभी बिक्रियां सूचित की हैं। उसने हवाफोन द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के माध्यम से भी परिशिष्ट-2 में भारत को कोई निर्यात सूचित नहीं किया है। उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसने आरएचटी के माध्यम से भारत को सामानों का निर्यात किया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हवाफोन और आर.एच.टी. द्वारा प्रस्तुत सूचना में कोई मेल नहीं है।

43. अतः उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी हवाफोन द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार नहीं करते। तदनुसार, हवाफोन के लिए निर्यात कीमत प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर है।

जियांगजिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण (उत्पादक/निर्यातक)

44. जियांगजिन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कंपनी लिमिटेड चीन जन.गण (“जे एक्स एस एस”) द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि जे एक्स एस एस ने 6 एमएम. से अधिक मोटाई वाली प्लेटों का निर्यात किया है और वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। अतः जे एक्स एस एस द्वारा प्रस्तुत सूचना के लिए कोई जांच नहीं की जाती है।

चीन जन.गण. से असहयोगी उत्पादकों एवं निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

45. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों सहित चीन जन.गण. में सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, जिनके उत्तर प्राधिकारी ने स्वीकार नहीं किए हैं, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध सामानों के लिए भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की है और वह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

यूरोपीय संघ में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है। यूरोपीय संघ में सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर संबद्ध सामानों की तरह भारित औसत निर्यात कीमत निर्धारित की है। और उसे नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

पाटन मार्जिन

47. भारत ने निर्यात कीमत (निर्यातक द्वारा दावा किए गए सभी समायोजनों का निवल तथा प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई) की तुलना पाटन मार्जिन निर्धारित करने के लिए सामान्य मूल्य से की गई है। संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच की अवधि के दौरान पाटन मार्जिन निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए अनुसार निर्धारित किया गया है :

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	सामान्य मूल्य अमेरिकी डॉलर	निवल निर्यात कीमत अमेरिकी डॉलर	पाटन मार्जिन अमेरिकी डॉलर	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन रेंज %
(ठ)	चीन जन.गण	सभी	सभी	***	***	***	***	50-60
(ड)	यूरोपीय युनियन	सभी	सभी	***	***	***	***	70-80

48. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन काफी है तथा संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी उत्पादकों-निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंधों का निर्धारण

49. अनुबंध-11 के साथ पठित पाटन रोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए” क्षति के निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग के लिए क्षति को दिखा सकते हैं। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करते हुए इसकी जांच करना जरूरी समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से कीमत में काफी कमी हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी सीमा तक कीमतों को अन्यथा कम करना अथवा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी।

घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों के संबंध में निर्यातक आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

50. क्षति संबंधी मुद्दों के संबंध में विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित हैं :-

- (क) याचिका में पाटन एवं क्षति का पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
- (ख) घरेलू उद्योग का निष्पादन स्थिर रहा है और उसमें सुधार हुआ है। पहुंच मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत कटौती कम हुई है, घरेलू उद्योग का उत्पादन तथा क्षमता उपयोग बढ़ा है।
- (ग) क्षति घरेलू उद्योग के प्रतिकूल निर्यात निष्पादन के कारण हुई है। क्षति चीन जन.गण. से आयातों के अलावा, अन्य कारकों के कारण हुई है।
- (घ) पूर्व प्रभावी उपायों के लिए मांग अनावश्यक है।
- (ङ) चीनी आयात कुल आयात का 84 प्रतिशत है इसे देखते हुए प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में संचयन उपयुक्त नहीं है।
- (च) घरेलू उद्योग को इस कारण क्षति नहीं हुई है कि आर्थिक मानदंड या तो सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं अथवा अधिकतर स्थिर हैं। उत्पादन मांग, बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग बढ़े हैं।
- (छ) घरेलू उद्योग को हानि हो रही है परंतु क्षति निर्धारण के लिए मानी गई अवधि के आरंभ में 2012-13 में उसे पहले ही हानि हो रही थी।
- (ज) क्षति अन्य कारकों के कारण हुई है जिनकी प्राधिकारी को जांच करनी है।
- (झ) घरेलू उद्योग को क्षति निर्धारण के लिए मानी गई अवधि के आरंभ से लाभ नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ताओं को पहले ही 2012-13 में हानियां हो रही थी।
- (ञ) घरेलू उद्योग का निष्पादन में लगभग 50 प्रतिशत उतार-चढ़ा के उपयोग दर के साथ दक्षता की समस्या है। निवेश करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्णय से क्षति हुई है।
- (ट) पाटनरोधी उपाय लगाने से कीमत वृद्धि होगी, जो जनहित में नहीं है।

घरेलू उद्योग के विचार

51. घरेलू उद्योग के द्वारा क्षति संबंधी मुद्दों के बारे में निवेदन और प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दे निम्नलिखित हैं :-

- क. जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।
- ख. संबद्ध वस्तुओं के आयातों में उत्पादन के संदर्भ में तथा भारत में खपत के संदर्भ में भी बढ़ोतरी हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है, यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण यह है कि आयातों ने मांग में बढ़ोतरी को बुरी तरह से जकड़ लिया है और संबद्ध देशों से आयातों के बाजार हिस्से में 2012-13 से पी ओ आई (क) में तेजी से बढ़ोतरी हुई।
- घ. घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप उत्पादन और बिक्रियों में बढ़ोतरी नहीं कर सका है।
- ङ. घरेलू उद्योग की सामान सूचियों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद अपनी बिक्रियों को बढ़ा नहीं सका है। आयात भारत में मांग को बुरी तरह से जकड़ रहा है।
- च. भारत में कम कीमत वाले पाटित आयातों की वजह से कीमत में काफी कमी और नियंत्रण है।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय अत्यधिक प्रभावित हुई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय, निवल लाभों और नकद लाभों में नकारात्मक प्रवृत्ति हुई है और पी ओ आई के दौरान हानियां भी अत्यधिक हुई हैं।
- ज. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर काफी प्रभाव पड़ा है। लाभप्रदता में पूरी क्षति अवधि के दौरान नकारात्मक प्रवृत्ति रही है और जांच की अवधि के दौरान हानियां और अधिक बढ़ी हैं।
- झ. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति किसी तरह से प्रभावित नहीं हुई है। इसके अलावा, क्षति संबंधी मानदंडों की जांच करते समय याचिकाकर्ताओं ने निर्यातों से संबंधित सूचना की उपेक्षा की है और संपूर्ण क्षति विश्लेषण आवेदकों के घरेलू निष्पादन पर ही आधारित है।
- ञ. विश्लेषण बहुत अधिक यह दर्शाता है कि भारत में विचाराधीन उत्पादन के बढ़ते हुए पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में बढ़ोतरी और घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के बीच में सशक्त संबंध है।

- ट. हितबद्ध पक्षकारों ने यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति अन्य कारकों तथा अधिक क्षमताओं के कारण है। ये दावे बहुत आम हैं और समर्थन करने हेतु किन्हीं तथ्यों और आंकड़ों के बिना हैं। भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की वजह से क्षति हो रही है, इस तथ्य की पहचान ही पुष्टि हो गई है। घरेलू उद्योग बहुत वर्षों से अस्तित्व में है और विगत में अच्छा कर रहा है।

प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच

52. क्षति और कारणात्मक लिंक के बारे में जांच की अवधि के बारे में घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदनों और प्राधिकारी के द्वारा प्रासंगिक समझे गए निवेदनों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया है :-
- क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के पहुंच मूल्य में काफी गिरावट आयी है और घरेलू उद्योग को उसे हो रही वास्तविक क्षति के कारण उन कम कीमतों से मेल करने के लिए विवश होना पड़ा है।
- ख. घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के बारे में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संपूर्ण क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के घरेलू निष्पादन पर ही आधारित है।
- ग. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का भी विश्लेषण किया कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति अन्य कारकों के कारण है। इन दावों का कोई समर्थक तथ्य एवं आंकड़े नहीं हैं।

संचयी मूल्यांकन

53. पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-II (iii) और विश्व व्यापार संगठन करार (डब्ल्यू टी ओ) के अनुच्छेद 3.3 में यह प्रावधान है कि यदि कहीं ऐसे देश से अधिक देशों से उत्पाद का आयात साथ-साथ किया जा रहा हो और उसे पाटनरोधी जांचों में रखा जा रहा हो, तो प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से मूल्यांकन करेंगे, यदि वह यह निर्धारित करे कि :
- (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत से अधिक अभिव्यक्त हो और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात के 3 प्रतिशत (या उससे अधिक) हो अथवा जहां अलग-अलग देशों से निर्यात 3 प्रतिशत से कम हो, सामूहिक रूप से आयात समान वस्तु के आयात के 7 प्रतिशत से अधिक बनता हो तथा
- (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों के आलोक में उपयुक्त है।
54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि :
- क. संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध सामानों का पाटन हो रहा है। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमों के तहत निर्धारित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- ख. प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा अलग-अलग आयात की कुल मात्रा के 3 प्रतिशत से अधिक है।
- ग. आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है क्योंकि संबद्ध देशों से निर्यात उन प्रत्येक देश द्वारा पेश समान वस्तुओं की सीधे ही प्रतिस्पर्धा ही नहीं करते अपितु, भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा पेश समान वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करते हैं।
55. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के निर्यात से संचयी रूप से घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा।
56. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।

पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

मांग का आकलन

57. संबद्ध वस्तुओं की मांग का निर्धारण समान उत्पाद के भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों को समस्त देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के साथ जोड़ कर किया गया है। वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त हुए आयात संबंधी आंकड़ों पर भरोसा किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है :-

विवरण (एम टी में)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015-दिसं, 2015 (ए)	पीओआई (जुलाई 2015- दिसं 15)	पीओआई (ए)
संबद्ध देश कुल पाटित आयात	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
अन्य देशों से आयात	41	304	0	192	0	0
कुल आयात	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
याचिकाकर्ताओं की घरेलू बिक्री	230,213	327,096	308,076	415,032	189,723	379,446
अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री	225,874	171,790	192,146	225,007	109,928	219,857
कुल मांग/ स्पष्ट खपत	516,898	573,045	710,117	1,052,552	512,963	1,025,925

आयात मात्रा और संबद्ध देशों का हिस्सा

58. पाटित आयातों की मात्रा के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह विचार करना होता है कि क्या पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि पूर्णतः हुई है अथवा भारत में उत्पादन अथवा खप के संदर्भ में हुई है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा के बारे में निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :-

विवरण (एम टी में)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर, 2015 (ए)	पीओआई(जुलाई 2015- दिसंबर, 15)	पीओआई (ए)
संबद्ध देश से पाटित आयात	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
प्रवृत्ति	100	122	345	678	351	702
अन्य देशों से आयात	41	304	0	192	0	0
प्रवृत्ति	100	748	-	471	-	-
कुल आयात	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
प्रवृत्ति	100	122	345	678	351	702
कुल मांग/ स्पष्ट खपत	516,898	573,045	710,117	1,052,552	512,963	1,025,925
प्रवृत्ति	100	111	137	204	99	198
खपत के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयात	12%	13%	30%	39%	42%	42%
याचिकाकर्ताओं का उत्पादन	414,910	576,975	559,218	591,385	277,318	554,636
याचिकाकर्ताओं के कुल उत्पादन के संदर्भ में संबद्ध देश से पाटित आयात	15%	13%	38%	70%	77%	77%

59. उपर्युक्त सारणी में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं :-

- क. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात अबाध रूप से वर्ष 2012-13 में 60771 एम टी से बढ़कर पी ओ आई (क) में 426622 एम टी हो गया।
- ख. याचिकाकर्ताओं के उत्पादन के संदर्भ में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत से बढ़कर पी ओ आई (क) में 77 प्रतिशत हो गए।

ग. भारत में खपत के संदर्भ में चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात वर्ष 2012-13 में 12 प्रतिशत से बढ़कर पी ओ आई (क) में 42 प्रतिशत हो गया है।

60. इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात पूर्ण मात्रा में और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में दोनों दृष्टि से बढ़ा है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत-प्रभाव

61. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध-11 (ii) में निम्नानुसार निर्धारित है :

“जहां तक नियम 18 के उप नियम (2) में किए गए उल्लेखानुसार कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमत में होने वाली वृद्धि में अन्यथा काफी अधिक ह्रास हुआ है अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हो गई होती।”

62. यह जांच की गई कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत का पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव काफी सीमा तक कीमतों को अन्यथा कम करना अथवा कीमतों में बढ़ोतरी को रोकना है, जो काफी हद तक अन्यथा हुई होगी। घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में कीमत में कटौती, कीमत पर दबाव और कीमत नियंत्रण के संदर्भ में जांच की गई है।

कीमत कटौती

63. क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की है। इस संबंध में समान सूत्र के ट्रेड के बारे में उत्पाद के पहुंच मूल्य की सभी प्रकार की छूट और करों को निकाल कर घरेलू उद्योग के औसत विक्रय मूल्य के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण फैक्ट्री से बाहर के सूत्र पर किया गया था। घरेलू कीमतों और कटौती का मार्जिन नीचे सारणी में दर्शाया गया है:-

कीमत कटौती	जुलाई 15 से दिसंबर 15	चीन जन.गण	ईयू
पहुंच मूल्य	रू./मी.ट.	40,761	35,801
घरेलू बिक्री कीमत	रू./मी.ट.	***	***
कीमत कटौती	रू./मी.ट.	***	***
कीमत कटौती	एलवी का %	***	***
कीमत कटौती रेंज		20-30%	35-45%

64. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से नोट करते हैं कि चीन जन.गण. तथा यूरोपीय संघ के लिए काफी कीमत कटौती है।

कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण

65. क्या पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतें नियंत्रित हुई हैं, अथवा कीमतों में बढ़ोतरी रूकी है, जो काफी हद तक हुई होगी, इसका निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में हुए परिवर्तनों के बारे में विचार किया। स्थिति नीचे दी गई सारणी में दर्शायी गयी है :-

विवरण (रूपए प्रति मी.ट.)	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर, 2015	पीओआई (जुलाई 2015- दिसंबर 15)
निर्माण एवं बिक्री लागत	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	100	104	106	95	94
घरेलू बिक्री कीमत	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	100	104	105	93	91
पहुंच मूल्य	41,440	45,340	45,338	41,501	40,372
प्रवृत्ति	100	109	109	100	97

66. यह नोट किया जाता है कि घरेलू बिक्री कीमत में कमी बिक्री लागत में कमी की अपेक्षा अधिक है। आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों तथा क्षति जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए निर्माण एवं बिक्री की लागत की अपेक्षा काफी कम रही है। कम कीमत के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग वह बिक्री कीमत नहीं ला पाया है जिससे यहां तक कि उसकी लागत वसूल हो जाए। इस प्रकार आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा था।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

67. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 11 में यह अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणाम प्रभाव की एक वस्तुपरक जांच करना शामिल होगा। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभों, उत्पादन, बाजार शेयर, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ, क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, सामान सूचियों, रोजगार, मजदूरियों, विकास, पूंजी निवेशों को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों को शामिल करते हुए उद्योग की स्थिति को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन करना शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों के बारे में नीचे विचार किया है :-

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

68. उत्पादक, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार था :-

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	पीओआई (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	पीओआई (ए)
संस्थापित क्षमता(मी.ट.)	7,15,000	10,73,000	10,83,000	10,83,000	5,41,500	10,83,000
कुल उत्पादन(मी.ट.)	4,14,910	5,76,975	5,59,218	5,91,385	2,77,318	5,54,636
क्षमता उपयोग	58%	54%	52%	55%	51%	51%
घरेलू बिक्री	2,30,213	3,27,096	3,08,076	4,15,032	1,89,723	3,79,446

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि संबद्ध सामानों का घरेलू उत्पादन बढ़ा है, तथापि, पाटित आयातों में पर्याप्त वृद्धि से घरेलू उद्योग क्षति जांच अवधि के दौरान ईष्टतम क्षमता उपयोग प्राप्त नहीं कर पाया।

लाभप्रदता

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015- दिसंबर 2015 (ए)	पीओआई (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	पीओआई (ए)
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (करोड़ रूपए में)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	(100)	(150)	(166)	(253)	(127)	(254)
पीबीटी (रू./मी.ट.)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	(100)	(106)	(124)	(140)	(153)	(153)
नकद लाभ(पीबीटी+ मूल्यहास) (करोड़ रूपए में)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)

प्रवृत्ति	(100)	(133)	(174)	(282)	(144)	(287)
नकद लाभ (रू./मी.ट.)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	(100)	(94)	(130)	(156)	(174)	(174)

70. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से निम्नलिखित नोट करते हैं :

- क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा पाटन बढ़ाए जाने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हानियां काफी बढ़ी हैं।
- ख. पी ओ आई के दौरान संबद्ध देशों से पाटन की वजह से घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर उचित लाभ अर्जित करने के बजाय बिक्रियों की लागत को वसूल नहीं कर सका है।

लगाई गई पूंजी पर आय

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (ए)
आरओसीई	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	100	(471)	(802)	111

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग पूरी क्षति जांच अवधि में लगाई गई पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाया है। जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से भारी पाटन के कारण घरेलू उद्योग वह बिक्री कीमत नहीं ला पाया है जिससे लगाई गई पूंजी पर उसे उपयुक्त आय हो सकती है।

बाजार हिस्सा

72. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की नीचे दिए अनुसार जांच की गई है :-

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	अप्रैल 2015-दिसंबर 2015 (ए)	पीओआई (जुलाई 2015- दिसंबर 15)	पीओआई (ए)
मांग (मी.ट.)	516,898	573,045	710,117	1,052,552	512,963	1,025,925
सूचीबद्ध	100	111	137	204	99	198
बाजार हिस्सा						
याचिकाकर्ताओं का हिस्सा	45%	57%	43%	39%	37%	37%
अन्य सभी उत्पादकों का हिस्सा	44%	30%	27%	21%	21%	21%
संबद्ध देशों का हिस्सा	12%	13%	30%	39%	42%	42%
अन्य देशों का हिस्सा	0%	0%	0%	0%	0%	0%

73. प्राधिकारी उपर्युक्त तालिका से यह देखते हैं कि संबद्ध सामानों के लिए भारत में मांग बढ़ने पर भी घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हुआ है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात का बाजार हिस्सा क्षति अवधि में बढ़ा है। यह इस कारण है कि आयातों की मांग में भारी वृद्धि हुई है।

74. घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आ रहे पाटित आयातों की भारी मात्रा के कारण मांग में वृद्धि के अनुरूप विचाराधीन उत्पाद की बिक्री नहीं बढ़ा पाया है।

मालसूची :

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (जुलाई 2015- दिसंबर 15)
औसत मालसूची (मी.ट.)	27,044	36,707	38,220	61,980
प्रवृत्ति (सूचीबद्ध)	100	136	141	229

75. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अधिक हो रही सामान सूचियों की स्थिति का सामना कर रहा है। आधार वर्ष की तुलना में सामान सूचियों के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आयातों में बढ़ोतरी होने की वजह से घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा कम हो गया है और बड़ी हुई मांग पर आयातों द्वारा कब्जा कर लिया है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग अपना उत्पादन और बिक्री नहीं बढ़ा पाया है जिससे क्षति अवधि में मालसूची एकत्रित होने की स्थिति बन गई है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उत्पादकता में हास से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। नीचे दी गई सारणी में यह देखा जा सकता है कि उत्पादकता 2012-13 में 100 सूचीबद्ध प्वाइंटों से बढ़कर पी ओ आई के दौरान 145 सूचीबद्ध प्वाइंट हो गई है।

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादकता	396	551	532	575
प्रवृत्ति	100	139	134	145

वृद्धि

विवरण	इकाई	2013-14	2014-15	पीओआई (ए)
उत्पादन की लागत	%	4%	2%	-11%
बिक्री कीमत	%	4%	1%	-13%
हानि	%	50%	11%	53%
नकद हानि	%	33%	31%	65%
बाजार हिस्सा	%	12%	-24%	-15%

77. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभप्रदता बाजार हिस्सा और बिक्री कीमत के बारे में घरेलू उद्योग का विकास नकारात्मक रहा है।

पूंजी निवेश जुटाने की सामर्थ्य

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी ने काफी निवेश किया है। तथापि, इन निवेशों के बावजूद, घरेलू उद्योग के निष्पादन में काफी कमी (विकृति) हो गई है और अतिरिक्त निवेश काफी तरह से प्रभावित हो सकता है।

पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर

79. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर देश में आ रहे हैं और पाटन मार्जिन काफी है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

80. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक आदि यह दर्शाते हैं कि जापान को छोड़कर संबद्ध देशों से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत से कम है और सभी संबद्ध देशों से आयातित सामानों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम है जिससे भारतीय बाजार में काफी कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत हास तथा कीमत न्यूनीकरण हो रहा है। इस प्रकार, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य है।

81. इस प्रकार, यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पूरी तरह पाटित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। आयात भारत में उत्पाद की खपत और उत्पादन के संबंध में काफी बढ़ा है। इस प्रकार, आयात संपूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में बढ़े हैं। पाटित आयातों का कीमत न्यूनीकरण, कीमत हास और कीमत कटौती के संदर्भ में काफी प्रतिकूल कीमत प्रभाव रहा है। संबद्ध सामानों की घरेलू कीमतों को कम करने के लिए पाटित आयातों का प्रभाव रहा है। कम कीमत वाले पाटित आयातों से घरेलू उद्योग उस बाजार कीमत को लाने के लिए मजबूर हुआ

है जिससे कि उसकी लागत भी नहीं आ सकती। घरेलू उद्योग कम कीमत पर बिक्री का सामना करना पड़ रहा है। भारत में आ रहे कम कीमत के पाटित आयातों के कारण काफी कीमत ह्रास एवं न्यूनीकरण है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन काफी महत्वपूर्ण है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और लगाई गई पूंजी पर आय पर जांच की अवधि के दौरान प्रभाव पड़ा है।

कारणात्मक संपर्क :

82. प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग की क्षति हुई है। घरेलू उद्योग के लिए पाटन और वास्तविक क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की जांच निम्नानुसार की गई है :-

तीसरे देशों से आयात

83. संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से आयात पर्याप्त मात्रा में है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति अथवा खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जिन कीमतों पर अन्य देशों से सामान आ रहे हैं, वे कीमतें उन कीमतों से कहीं अधिक हैं, जिन पर संबद्ध देशों से सामान आ रहे हैं।

मांग में कमी

84. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है। तदनुसार, मांग में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति होने का कारण नहीं हो सकता है। वास्तव में, घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी के अनुरूप अपनी बिक्री और बाजार हिस्से में बढ़ोतरी नहीं कर सका है।

विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा और उनके बीच में व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार संबंधी ऐसी कोई प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

प्रौद्योगिकी में विकास

86. संबंधित उत्पाद के उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी में विकासों को घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारक माना जा सकता है।

खपत के पैटर्न में बदलाव

87. घरेलू उद्योग इस किस्म की वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनका भारत में आयात किया गया है। खपत के पैटर्न में संभावित बदलाव ऐसे कारक नहीं हैं जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति होने का दावा किया जा सके।

निर्यातनिष्पादन

88. घरेलू उद्योग के लिए दावा की गई क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभव पर्याप्त विकृति से नहीं है। वास्तव में, घरेलू उद्योग के द्वारा निर्यातों में वस्तुतः गिरावट नहीं हुई है। किसी मामले में प्राधिकारी ने, जहां कहीं संभव हुआ, घरेलू निष्पादन के बारे में विचार किया है।

अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में प्राधिकारी के द्वारा किए गए आकलन पर प्रभाव नहीं पड़ा है। प्राधिकारी के द्वारा विचार की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के बारे में है।

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में ह्रास से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

कारणात्मक संपर्क से संबंधित तथ्य

91. क्षति की अवधि में पाटित आयातों के विश्लेषण और घरेलू उद्योग के निष्पादन से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं:-

(क) जांच की संपूर्ण अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।

(ख) संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में उत्पादन के संदर्भ में तथा भारत में खपत के संदर्भ में भी पूर्णतः बढ़ोतरी हुई है।

- (ग) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में कमी हुई है, यद्यपि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण यह है कि आयातों ने मांग में बढ़ोतरी को बुरी तरह से जकड़ लिया है।
- (घ) घरेलू उद्योग की सामान सूचियों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद अपनी बिक्रियों को बढ़ा नहीं सका है। आयातों से भारत में मांग में भारी वृद्धि हो रही है।
- (ङ) भारत में कम कीमत वाले पाटित आयातों की वजह से कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण है।
- (च) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अत्यधिक प्रभावित हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हुई हानियां काफी बड़ी हैं।

क्षति एवं कारण

92. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में उपरोक्त जांच से प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है। समस्त क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में तथा भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पूर्णरूपेण वृद्धि हुई है। पाटित आयातों ने बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। संबद्ध देशों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और इसे अत्यधिक माना गया है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों ने उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। संबद्ध आयातों के बाजार के हिस्से में अत्यधिक वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ के संबंध में अत्यधिक गिरावट आई है। उसकी मांग सूचियों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी का अनन्तिम रूप से यह निष्कर्ष है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को आर्थिक क्षति हुई है।
93. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की है। क्षति मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किए गए हैं:-

क्षति मार्जिन

क्र.सं.	देश	उत्पादक	निर्यातक	एनआईपी अमेरिकी डॉलर	पहुंच मूल्य अमेरिकी डॉलर	क्षति मार्जिन अमेरिकी डॉलर	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज %
(ढ)	चीन जन.गण.	सभी	सभी	***	***	***	***	30-40
(ण)	ई यू	सभी	सभी	***	***	***	***	45-55

94. यथा निर्धारित पाटन मार्जिनों और क्षति मार्जिनों का सूत्र पर्याप्त है।

ट. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध

95. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उसमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच के दौरान पहले ही उठाए गए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है:

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

96. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध सारांश में नीचे दिए गए हैं:

- (क) संबद्ध जांच में परिकलित क्षति रहित कीमत कम उल्लिखित की गई प्रतीत होती है। विशेष रूप से जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लि. ("जेएससीपीएल") और एस्सार स्टील इंडिया लि. ("एस्सार") के लिए परिकलित एनआईपी कम उल्लिखित की गई है।
- (ख) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बताई गई गोपनीय एनआईपी कार्यशीट से घरेलू उद्योग समझता है कि जेएससीपीएल के लिए एनआईपी जेएससीपीएल द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों के लिए इनपुट लागत के रूप में एचआर कॉइलों के लिए अंतरण कीमत (बाजार कीमत होने के नाते) पर विचार कर परिकलित की गई है। एचआर कॉइलों के लिए अंतरण कीमत भारत में आ रही एचआर कॉइलों के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान बहुत कम थी। इस प्रकार मानी गई अंतरण कीमत एचआर कॉइलों की उत्पादन लागत को भी पूरा नहीं करती, उपयुक्त आय को तो छोड़ ही दें, जिससे जेएससीपीएल के लिए एनआईपी कम रखी

गई है। अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि संबद्ध सामानों के विनिर्माण के लिए इनपुट के रूप में जेएससीपीएल द्वारा प्रयुक्त एचआर कॉइलों के विनिर्माण के लिए लगाई गई पूंजी पर आय तथा पूर्ण लागत पर विचार किया जाए।

- (ग) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बताई गई गोपनीय एनआईपी कार्यशीट से यह समझ में आता है कि एस्सार के लिए लगाई गई पूंजी पर आय का परिकलन करते समय निम्न निर्धारित परिसंपत्तियों से कुछ कटौतियां की गई हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया था कि:
- निर्दिष्ट प्राधिकारी को लेखा परीक्षित लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार एस्सार के लिए सभी परिसंपत्तियों पर विचार करना चाहिए।
 - सभी धनराशियां इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी संगत लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखा बहियों में पूंजीबद्ध की गई हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए लेखा परीक्षित लेखा बहियों से बाहर जाने और स्वैच्छिक आधार पर किसी राशि को अनुमति न देने का कोई कारण नहीं है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा लगाई गई परिसंपत्तियों से ऐसी कोई कटौती करने की अनुमति देता हो।
 - यह भी अनुरोध किया गया था कि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई कटौतियां पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के विपरीत हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी का दृष्टिकोण स्वैच्छाचारी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में है। उपर्युक्त मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए और सभी निम्न अचल परिसंपत्तियां एनआईपी का परिकलन करने में मानी जानी चाहिए।
- (घ) घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि संदर्भ कीमत पर आधारित शुल्क से भारत में संबद्ध सामानों की आयात मात्रा पर पर्याप्त रोक नहीं लग पाई है। संबद्ध देश से आयात अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी काफी रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी जानकारी में आया है कि आयात कीमतें जांच की अवधि के बाद इनपुट लागत में काफी वृद्धि होने के बावजूद अनंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित संदर्भ कीमत के आसपास ही रही हैं। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए अंतिम जांच परिणाम में निर्धारित शुल्क की सिफारिश करें। शुल्क के निर्धारित रूप को लागू करने से उपायों की प्रभावकारिता सुनिश्चित होगी क्योंकि इससे कीमत में हेराफेरी अथवा प्रवंचना की संभावना कम होगी।
- (ङ) संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे अन्य देशों द्वारा लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का स्तर उनके संबंधित घरेलू उद्योगों के सामने आ रही भारी पाटन और क्षति के आलोक में कलर कोटेड स्टील उत्पादों के आयात पर बहुत अधिक है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

97. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सारांश में निम्नलिखित हैं:
- (क) यह अनुरोध है कि झांगजियागांग शांजिग हैवी प्लेट कं. लि., चीन जन गण (उत्पादक) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की जांच नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उसने 6 एमएम से अधिक मोटाई वाली प्लेटों का निर्यात किया है और वे जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आती हैं।
- (ख) झांगजियागांग शांजिग हैवी प्लेट कं. लि. के लिए पाटन मार्जिन हेतु अलग मूल्यांकन उपयुक्त नहीं है।
- प्राधिकारी द्वारा जांच**
98. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध प्रकृति में पुनरावृत्ति हैं और उन्हें पहले ही प्रकटन विवरण में हल कर दिया गया है। उपर्युक्त जांच परिणाम यथा तथ्यतः पक्षकारों के इन तर्कों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नलिखित रूप में उस सीमा तक जांच की है जहां तक वे संगत हैं और अन्यत्र जिनका समाधान नहीं किया गया है:
- (क) मैसर्स झांगजियागांग शांजिग हैवी प्लेट कं. लि., चीन जन गण (उत्पादक) और उसके व्यापारी मैसर्स जियांग्सू शागांग इंटरनेशनल ट्रेड कं. लि., चीन जन गण और मैसर्स शागांग इंटरनेशनल (सिंगापुर) पीटीई. लि., सिंगापुर ने प्रकटन विवरण के उत्तर में सूचित किया है कि उन्होंने भारत को 6 एमएम की मोटाई से अधिक की भारी प्लेटें निर्यात की हैं जो कि विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि, इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यातित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के भीतर शामिल नहीं हैं, अतः उनकी चिंता का प्राधिकारी ने पहले ही समाधान कर दिया है।
- (ख) जहां तक क्षति रहित कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग की चिंताओं का संबंध है, प्राधिकारी यह देखते हैं कि क्षति रहित कीमत का परिकलन पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है।
- (ग) संदर्भ कीमत की बजाए निर्धारित शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करने के लिए घरेलू उद्योग

के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध सामानों के लिए संदर्भ कीमत आधारित शुल्क का रूप उपयुक्त है।

ठ. भारतीय उद्योग का हित एवं अन्य मुद्दे

99. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य रूप में पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो कि देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लगाने से किसी भी तरह से संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और इसीलिए ग्राहकों को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
100. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित शुल्क लगाने से ग्राहक के लिए महत्वहीन लागत प्रभाव होंगे। अतः भारतीय बाजार में स्वच्छ प्रतिस्पर्द्धा पाटनरोधी उपायों से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की परिपाटियों से उत्पन्न अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की बढ़ोत्तरी रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सिफारिशें

101. हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोध और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:
- (क) संबद्ध देशों से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम है।
- (ख) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध आयात के निमित्त वास्तविक क्षति हुई है।
- (ग) यह क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण हुई है।
102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी। पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्यहितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटन, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक पाटन मार्जिन तथा ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन एवं क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है।
103. कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि तथा संबद्ध सामानों के बीच अंतर के रूप में लगाने की सिफारिश करते हैं। बशर्ते कि पहुँच मूल्य कॉलम 8 में दर्शाए गए मूल्य से कम हो। इस प्रयोजन के लिए आयात का पहुँच मूल्य सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क के लागू स्तर पर होगा। यदि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो सिफारिश किए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की वैधता केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 11.01.2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अनंतिम शुल्क लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होगी।

शुल्क तालिका

क्रम सं.	शीर्ष/उप शीर्ष	वस्तुओं का विवरण*	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूनिट	करेंसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(घ)	7210, 7212, 7225 और 7226	कॉइलों में अथवा कॉइलों में नहीं, प्री-पैटेड, पैटेड, कलर कोटेड अथवा ऑर्गेनिक कोटेड फ्लेट स्टील, चाहे वे जिंक,	चीन जन गण	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	822	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

		एल्युमीनियम जिक के मैटेलिक कोटेड सबट्रेट अथवा अन्य कोई सबट्रेट कोटिंग हो							
(ड)	- वही -	- वही -	चीन जन गण	संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	822	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
(च)	- वही -	- वही -	संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन गण	कोई अन्य	कोई अन्य	822	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
(छ)	- वही -	- वही -	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	822	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
(ज)	- वही -	- वही -	यूरोपीय संघ	संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश	कोई अन्य	कोई अन्य	822	मी. टन	अमेरिकी डॉलर
(झ)	- वही -	- वही -	संबद्ध देश के अलावा कोई अन्य देश	यूरोपीय संघ	कोई अन्य	कोई अन्य	822	मी. टन	अमेरिकी डॉलर

***टिप्पणी-** सामानों के विवरण में 6 एमएम अथवा उससे अधिक की मोटाई की प्लेटें शामिल नहीं हैं।

104. केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिए जाने के बाद इस अंतिम जांच परिणाम के विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जाएंगी।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2017

FINAL FINDINGS

Sub: Anti-dumping investigation concerning imports of “Color coated / pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel” originating in or exported from China PR and European Union-reg.

F. No.14/28/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD rules) thereof M/s. Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited (hereinafter referred to as the “applicants” or “petitioners” or “domestic industry”) have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the AD Rules, for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Color coated / pre-painted flat products of alloy or non-alloy steel” (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR and European Union-reg. (hereinafter also referred to as the subject countries), and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. The Authority on the basis of sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant issued a public notice dated 29th June 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, in accordance with Rule 6(1) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
3. The Authority vide Preliminary Findings issued vide Notification No.14/28/2016-DGAD dated 20.10.2016 recommended provisional anti-dumping duty in the present investigation. Further, the Authority issued a Corrigendum to the aforementioned Preliminary Findings, vide Notification No 14/28/2016-DGAD dated 30.11.2016. Ministry of Finance issued a customs notification imposing provisional anti-dumping duty vide Customs Notification No. 02/2017-Customs (ADD) dated 11.01.2017 accepting the recommendations of the Authority.

A. Procedure

4. The procedure described below has been followed:
 - a. The Authority notified the Delegation of the European Union to India and the Embassy of China PR in India about the receipt of application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the AD Rules.
 - b. The Authority sent copy of initiation notification to the Delegation of the European Union to India and the embassy of China PR in India, known producers/ exporters from the subject countries and known importers/ users/ associations of the subject goods as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
 - c. The Authority forwarded copy of the non-confidential version of the application to the Delegation of the European Union to India and the embassy of China PR in India, known producers/exporters from the subject countries and known importers of the subject goods, in accordance with the AD Rules. A copy of the application was also provided to other interested parties, wherever requested.
 - d. The Delegation of the European Union to India and the embassy of China PR in India were also requested to advise the producers/exporters from their countries to file their responses within the prescribed time limits.
 - e. The Authority sent exporter's questionnaires to elicit relevant information to the following known exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:

European Union (EU)

1. Steel Coat Europe Alleur (Arcelor Mittal)
2. ThyssenKrupp Steel Europe AG
3. Tata Corus
4. SSAB
5. Metal Trade Comax
6. Voestalpine AG

China PR

1. Shanghai Metal Corporation
 2. Baosteel Group Corporation
 3. Sino East Steel Enterprise Co. Ltd
 4. Qingdao Sino Steel Co. Ltd
 5. Shanghai Color Steel Co. Ltd
- f. In response to the initiation notification, the following exporters/producers from the subject countries and traders have filed exporter's questionnaire:

China PR

1. Shandong Hwafone Steel Co. Ltd. (Producer)
 2. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd. (Exporter)
 3. Zhnagjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd (Producer)
 4. Shagang International Singapore Pte Ltd (Exporter)
 5. Qingdao RHT Steel Co. Ltd. (Exporter)
 6. M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd (Producer/Exporter)
- g. None of the producers/exporters from China PR has claimed Market Economy Treatment (MET) rebutting the non-market economy treatment in the present investigation. However, the Ukrainian producer has claimed market economy treatment. The same has been dealt with at appropriate place in the disclosure statement.
- h. Questionnaires were sent to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
1. Sungreen Ventilation Systems (P) Limited
 2. Shree Rama Steel Syndicate,
 3. Indian Pipes Pvt. Ltd.
 4. Metal Shine Roofing,
 5. Brijlal & Sons
 6. Kumar Corporation
 7. Oriental Metals India Pvt. Ltd.
 8. M.K.K. Metal Sections Pvt Ltd
 9. Kusum Metals Pvt Ltd
 10. Steel Co,
 11. Shanker Mercantile Pvt Ltd
 12. G M Traders
 13. PB Traders Private Limited
 14. Whirlpool of India Ltd.
 15. Samsung India Electronics Pvt.Ltd.
- i. None of the importers/users of the subject goods has filed questionnaire response or provided comments to the initiation of the investigation except Whirlpool of India Ltd.
- j. Further, the following parties have filed submissions/comments during the course of investigation:
1. Delegation of European Union to India

2. Whirlpool of India Ltd
 3. Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd, China PR
 4. China Chamber of International Commerce
 5. Zhnagjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd (Producer)
 6. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd. (Exporter)
 7. Shagang International Singapore Pte Ltd (Exporter)
 8. Shandong Hwafone Steel Sheet Co., Ltd., China PR (Producer)
 9. Qingdao RHT Steel Co. Ltd. (Exporter)
- k. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all interested parties have been taken into account in the present disclosure statement.
- l. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- m. Further information was sought from the applicant and other interested parties to the extent deemed necessary.
- n. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- o. The Non-Injurious Price (hereinafter referred to as 'NIP') is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-Dumping Rules. It has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- p. The applicants proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the dumping margin. However, keeping in mind the factual matrix of the case the authority has not adopted PCN to PCN comparison.
- q. Verification of the information provided by the applicant domestic industry was carried out by the Authority to the extent deemed necessary and only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- r. Investigation was carried out for the period starting from 1st July 2015 to 31st December 2015 (6 months) (hereinafter referred to as the 'period of investigation' or the 'POI'). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2012-13, 2013-14, 2014-15, April 2015 to December 2015 and the POI.
- s. The petitioners had submitted the petition alleging dumping of the subject goods from the subject countries relying upon transaction wise imports data sourced from IBIS. However, request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past three years, including the period of investigation. The Authority has relied upon the transaction-wise DGCI&S import data.
- t. Arguments raised and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority.
- u. Exchange rate for conversion of US\$ to INR is considered for the POI as INR 65.93 as per customs data.

- v. In this notification, *** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- w. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 4th May, 2017. All the parties attending the oral hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally by 9th May, 2017. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders by 15th May, 2017.
- x. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation which have formed the basis of the Final Findings was issued to the interested parties on 12.08.2017. The post Disclosure Statement submissions received from the domestic industry and other interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings Notification.

B. Product under Consideration and Like Article

5. The product under consideration (PUC) in the present investigation is:

“Pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium-zinc or any other substrate coating.”

These steels are either of alloy or non-alloy steel whether or not of prime or non-prime quality, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profiles. These products are available in various paint qualities and a variety of paint colours whether or not pre-coated with primer or any other suitable material. These steels may either be painted on top surface of the steel sheet or on bottom surface or on both top and bottom surfaces. This product may be supplied with or without guard film / lamination.

- 6. PUC offers resistance to corrosion along with barrier protection. PUC is used in many applications and sectors including but not limited to construction, roofing, walling, panelling, cladding and decking, automotive, white goods & appliances and furniture etc.
- 7. The PUC is classified under tariff item 72107000, 72124000, 72259900 and 72269990 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the imports have also been observed in certain other ITC HS Codes viz. 72101110, 72101190, 72101210, 72101290, 72103010, 72103090, 72104100, 72104900, 72105000, 72106100, 72106900, 72109010, 72109090, 72121010, 72121090, 72122090, 72123090, 72125020, 72125090, 72126000, 72255030, 72259200 and 72261100. The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

B.1. Views of the Interested Parties

- 8. Submissions made by exporters, importers, users and other interested parties with regard to issues related to PUC and considered relevant by the Authority are, inter alia, as follows:
 - a. One of the exporters has submitted that they export middle or heavy plate with a thickness of 6mm or more to India which is painted with one kind of shop primer. This product is not covered within the scope of the PUC but even then they have filed exporter questionnaire response as a measure of abundant caution. There is difference between the applications of the PUC and product exported by the exporter. In general, the thickness of the PUC is less than 6mm.
 - b. Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd. has sought exclusion for ‘prime coated hot rolled non-alloy steel plates’. The following reasons have been advanced by Zhangjiagang for exclusion of its product:
 - i. The product manufactured by domestic industry follows IS 14246-2013 whereas Zhangjiagang follows BS EN 10025-3:2004.
 - ii. Different chemical and physical characteristics.
 - iii. The steel grade is different.
 - iv. Production process is different - There should be at least two layers of coating and should be baked but for the product exported by Zhangjiagang the extra production process are only blast cleaning and spraying the paint.
 - v. Sales price of product exported by Zhangjiagang is different.

B.2. Views of the domestic industry

9. The submissions made by the domestic industry (DI) and considered relevant by the Authority are as follows:

- a. Domestic Industry has submitted that PUC covers all coated products whether pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium-zinc or any other substrate coating. These steels are either of alloy or non-alloy steel whether or not of prime or non-prime quality, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profiles.
- b. With regard to the submission of the exporter that heavy plates with thickness of 6mm or more may be kept out of the PUC, the Domestic Industry submits that this contention may be accepted as these plates are already not covered within the scope of the PUC.
- c. The domestic industry submits that the authority has already held in the preliminary findings that plates of thickness 6mm or more does not form part of the product scope. The exclusion request made by Zhangjiagang is, therefore, devoid of any merit and does not require any further consideration.
- d. Even otherwise there is no merit in the legal arguments based on which exclusion request has been made by Zhangjiagang.
- e. The product under consideration covers primer-coated non alloy steel sheet. The fact that product exported by Zhangjiagang follows different product standards as compared to that of other exported products covered within scope of product under consideration cannot be any ground for exclusion. Likewise, difference in grade, physical characteristics, production process and sale price of the exported product from the other exported product which forms part of product under consideration cannot be the ground for exclusion from the scope of product under consideration.
- f. Zhangjiagang has attempted to only distinguish its product type based on certain parameters from other types of the product under consideration i.e. the imported product that is under investigation. However, at the minimum, the exporter seeking exclusion of the product under consideration has to identify and differentiate its product from the like domestic product in India. Zhangjiagang does not even claim such differences. It is also not the claim of Zhangjiagang that its product is not substitutable and directly competitive with the like domestic product. There is no averment that the domestic industry does not manufacture the like product - either in the first leg of the definition i.e. identical or alike in all respects to the product exported by them or in the second leg of the definition i.e. product having closely resembling characteristics. Thus, there is no rational for exclusion of such product from the scope of product under consideration.

B.3. Examination of the Authority

10. The submissions made by the interested parties and the domestic industry with regard to the PUC related issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- a. Domestic industry has submitted that the PUC covers steels either of alloy or non-alloy steel whether or not of prime or non-prime quality, either in the form of coils or plain sheets or profiled sheets including but not limited to trapezoidal, sinusoidal, corrugated or any other type of profiles. Accordingly, the PUC does not cover plates of thickness 6mm or more.
- b. The Authority has examined the request for exclusion by Zhangjiagang and it notes that plates of thickness 6mm or more have already been excluded from the scope of PUC and therefore their concern has already been addressed.
- c. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as follows: -"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation. On the basis of information on record and considering the submissions made by the interested parties, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and those imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially

substitutable. The consumers use the two interchangeably. The Authority holds that the products manufactured by the Applicants constitute like article to the subject goods being imported into India from the subject countries.

11. Accordingly, the Product Under Consideration under the investigation is “Pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminum-zinc or any other substrate coating excluding plates of thickness 6mm or more.”

C. Confidentiality

C.1. Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding the standing of domestic industry

12. Following are the issues raised by interested parties with respect to excessive confidentiality:
 - a. It is submitted that the domestic industry resorted to excessive confidentiality depriving the interested parties from offering meaningful comments which is completely against the confidentiality provisions provided in the AD Rules.
 - b. The applicant industry has kept considerable information confidential without providing any justifiable reasons like calculation of working capital, interest on term loan, depreciation, miscellaneous income, purchase and sales policy, inventory valuation, quality control procedure etc. This is not permissible under the Rules as can be seen from the provisions above.
 - c. The Petitioner failed to evaluate some of the relevant economic factors and indices listed in Rule 11 of the Rules & para IV of Annexure II thereof. Indexed data on unit price, total costs, investments, employment and stocks are not explicitly provided and analyzed in the narrative version of the Petition, which lacks a meaningful analysis.

C.2. Views of the Domestic Industry

13. Following submissions are made by domestic industry with respect to excessive confidentiality
 - a. Interested parties have objected to the grant of confidentiality over working capital, interest on term loans, overdue and compounding interest, rate of depreciation, income earned by the domestic industry, break up of cost, purchase and sales policy etc. All the aforesaid information are highly business sensitive in nature and the disclosure of such information will cause prejudice to the domestic industry. Also, as a matter of practice, none of the aforesaid information is disclosed by the authority in any anti-dumping investigation. There can be no doubt that such information need not be disclosed to all the other interested parties.
 - b. Interested parties merely allege that they are not able to fully understand the claims put forward by the domestic industry because of confidentiality claimed over costing information in the petition. Notwithstanding the fact that costing information of the domestic industry is business sensitive in nature and cannot be disclosed, interested parties have also failed to provide even a single instance of specific claim which it is unable to respond to due to unavailability of the information which is considered as confidential. Thus, there is no merit in the claim of interested parties who have merely listed information over which confidentiality is claimed without specifying the prejudice caused to them due to unavailability of such confidential information.

C.3. Examination by the Authority

14. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule(2),(3)(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) *The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

(3) *Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.*

15. Submissions made by the interested parties with regard to confidentiality are examined and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.

D. Domestic Industry and Standing

16. Rule 2 (b) of the AD rules defines the domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”

17. The application has been filed M/s Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited. The production of these aforesaid producers accounts for a major proportion of the total domestic production and is more than 50% of Indian production.

D.1. Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding standing of the domestic industry.

18. The calculation of the support to the Petition by Indian producers and the standing are not clear and the document relied upon for these calculations should be provided to the interested parties.

D.2. Examination by the Authority:

19. With regard to the issue that calculation of the support to petition and standing is not clear, the Authority notes that the application has been filed by M/s Essar Steel India Limited and M/s. JSW Steel Coated Products Limited and these producers account for a major proportion of the total domestic production. The share of these producers is more than 50% of Indian production as can be seen from the table below. Further, there are no supporters in the present application.

Production	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	April 15- Dec 15 (A)	POI (July 15- Dec 15)	POI (A)
Petitioners							
-Essar Steel India Ltd.	MT	***	***	***	***	***	***
-JSW Steel Coated Products Ltd.	MT	***	***	***	***	***	***
Petitioners Total Production	MT	414,910	576,975	559,218	591,385	277,318	554,636
Other producers	MT	407,090	303,025	348,782	320,615	160,682	321,364
Total Domestic production (based upon JPC data)	MT	822,000	880,000	908,000	912,000	438,000	876,000

20. Therefore, the Authority holds that the applicants command a major proportion of the production of the subject goods in India and for the purpose of this investigation the applicants satisfy the standing requirement in terms of Rule 5(3) and constitute the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

E. De Minimis Limits

21. As per the import data received by the Authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and the data furnished by the cooperating exporters from the subject countries, the imports of the subject goods from the subject countries are found to be above the *de minimis* level.

F. Miscellaneous issues

22. Various interested parties have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding the dumping and injury determination have been dealt in the appropriate places in this disclosure statement, the general issues raised by the parties to the investigation have been examined hereunder. For the sake of brevity, the submissions of the parties and issues raised therein have been summarized as follows:

F.1. Miscellaneous issues raised by the interested parties

- a. The POI "should be representative and as recent as possible". Deviations from the benchmarking one-year POI should be substantiated by the Petitioners and the Designated Authority by positive evidence which is not present in the current case. The POI of six months is too short for arriving at a conclusion and it should be at least one year.
- b. The information submitted in the Petition is not sufficient to initiate the investigation and certain data is wrongfully treated as confidential. The non-confidential summaries of confidential information are not detailed enough.
- c. The domestic industry has already received multiple protection in violation of the WTO Agreements:
 - Increase of customs duty
 - Minimum import price
 - Anti-dumping investigations on other steel products.
- d. The import data should be provided to the interested parties in MS Excel format.
- e. The ROCE of 22% for computing NIP is very high. Reliance is placed on the judgement of Hon'ble CESTAT in the case of Bridgestone Vs. Designated Authority.
- f. Imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods would accrue undue advantage to Domestic Industry and will not be in the larger interest of Indian industry.

F.2. Miscellaneous submissions made by the Domestic Industry and considered relevant by the Authority are as follows:

- a. Section 9A (3) of the Act is with reference to history of dumping of the product. The Petitioners request the Authority to recommend retrospective levy of anti-dumping duty on the subject goods because the conditions for retrospective levy of antidumping duty are fully satisfied.
- b. There is evidence of dumping of subject goods which is evident from the fact that many countries have initiated anti-dumping investigation against import of the subject goods. Massive dumping of PUC into India has taken place in a relatively short period of time causing injury to the domestic industry.
- c. Some interested parties are of the view that 22% return on capital employed is not justified in calculating non-injurious price. The domestic industry strongly objects to the above contention and submits that none of the interested parties have adduced evidence to demonstrate why 22% return on capital employed is not justified. In fact, in two recent CESTAT rulings, it has been observed that 22% return on capital employed is valid as per the consistent practice of the Designated Authority and the onus is on the party refuting it to demonstrate with evidence why 22% return is not justified. In this regard, the Designated Authority's attention is invited to CESTAT rulings in Merino Panel Products Ltd. v. Designated Authority, Final Order No. AD/A/53541/2015-CU[DB] dated 27 November 2015 and Eximcorp India Pvt. Ltd. v. Designated Authority, Final Order No. AD/A/53462/2016-CU[DB] dated 12 September 2016. In view of the above CESTAT orders, 22%

return on capital employed is valid in the present case and should be affirmed definitively in the final findings.

- d. Exporters are well aware that they are resorting to dumping which is causing injury to the domestic industry since import prices of PUC have reduced significantly as evident from the landed values for respective countries.

F.3. Examination by the Authority

23. Miscellaneous submissions made by the interested parties and considered relevant by the authority are examined and addressed as follows:

- a. With regard to the contention of the interested parties that period of investigation should be more than 6 months, the Authority notes that according to recommendation of committee on anti-dumping practices (WTO document no. G/ADP/6 dated 16 May 2000):

"...the period of data collection for dumping investigations normally should be twelve months, and in any case no less than six months, ending as close to the date of initiation as is practicable"

Therefore, in view of above recommendation, 6 months period can be taken as the POI. The Authority has taken six months POI in other investigations also in the past.

- b. With regard to issue that domestic industry has already received multiple protection in violation of the WTO Agreements, the Authority notes that it is only required to examine the situation as prescribed under AD rules. Further, there is no violation of WTO Agreements by increase in customs duty. Applicability of antidumping duty on other steel products does not mean that domestic industry is not suffering injury for PUC.
- c. MIP was introduced by Government of India as a temporary measure and was in force till 3rd December, 2016.
- d. With regard to issue that import data should be provided in MS-excel format, authority notes that it could be provided to stakeholders based on specific request provided they undertake to use the data for the purpose of the impugned investigation only.
- e. The Authority notes that the argument that imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods would accrue undue advantage to Domestic Industry is presumptuous and pre-mature. Anti-dumping investigations are based on facts and law to analyze and assess the magnitude of dumping and consequent injurious effect on the domestic industry and to recommend imposition of suitable and adequate antidumping measure to provide a fair and level playing field to the domestic industry.
- f. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of a public file.
- g. As regards the request for retrospective imposition of anti-dumping duty, Section 9A(3) of Customs Tariff Act provides as follows:

If the Central Government, in respect of the dumped article under inquiry, is of the opinion that

- i. *there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practices dumping and that such dumping would cause injury; and*
- ii. *the injury is caused by massive dumping of an article imported in a relatively short time which in the light of the timing and the volume of imported article dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the anti-dumping duty liable to be levied,*

the Central Government may, by notification in the Official Gazette, levy anti-dumping duty retrospectively from a date prior to the date of imposition of anti-dumping duty under sub-section (2) but not beyond ninety days from the date of notification under that sub-section, and

notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, such duty shall be payable at such rate and from such date as may be specified in the notification.

- h. Taking into account the facts of the case, the Authority does not find it appropriate to recommend retrospective imposition of anti-dumping duty.
- i. The Authority notes that none of the interested parties have provided any evidence as to why the return on capital employed for the purpose of computing non-injurious price should be less than 22%. Further, it is the standard practice of the Authority to take ROCE as 22%.
- j. The present investigation has been initiated on the basis of *prima facie* analysis of the information/data furnished by the applicant showing dumping of subject goods from the subject countries, injury to the applicant on account of the said dumping and causal link between the two. With regard to the contention of the opposing interested parties that the initiation of investigation is bad in law due to misleading data furnished by the applicant and improper evaluation of data by the Authority, the Authority notes that it *prima facie* satisfied itself about the accuracy and adequacy of information on the basis of information furnished by the applicants at the time of initiation.

G. Market Economy Treatment (MET), Normal Value, Export Price and Dumping Margin

G.1. NORMAL VALUE

24. Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Provisions relating to Non- Market Economy countries

25. Annexure-I to AD rules states as under:

7. *In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

8. (1) *The term “non-market economy country” means any country which the designated authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in sub-paragraph (3)*

(2) *There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an anti-dumping investigation by the designated authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non-market economy country*

Provided, however, that the non-market economy country or the concerned firms from such country may rebut such a presumption by providing information and evidence to the designated authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3)

(3) *The designated authority shall consider in each case the following criteria as to whether:*

(a) *the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;*

(b) *the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;*

(c) *such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and*

(d) *the exchange rate conversions are carried out at the market rate.*

Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph”.

G.2. Submissions made by Exporters, Importers, Users and other Interested Parties

26. Various submissions made by the interested parties with regard to MET, Normal value, export price and dumping margin and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
- While determining the normal value for China PR, domestic selling prices and cost of Chinese producers should be considered as China PR has transitioned to a market economy in December 2016 as per its accession protocol to the WTO.
 - The construction of the normal value is not appropriate. The cost of production used to construct the normal value is very high due to the low capacity utilization.
 - The construction of the normal value based on the domestic industry's data is not supported by enough evidence. In addition, an average dumping calculation based on the constructed normal value is too simplistic and does not reflect the different types of products.
 - The dumping and injury calculations should take into account different types of products and qualities.

G.3. Submissions made by the Domestic industry

27. Submissions made by the domestic industry with regard to MET, Normal value, export price and dumping margin during the course of the investigation and considered relevant by the Authority are as follows:
- The contention raised by interested parties that the Appellate Body in EC-Fastener provided strong justification for China to automatically obtain market-economy status is incorrect. There is no such observation in the Appellate Body Report. The Appellate Body Report was adopted by the WTO DSB on 28 July 2011 i.e. five years before the date of expiry of 11 December 2016. In EC-Fastener, imposition of definitive anti-dumping duties by the EU on imports of certain iron or

steel fasteners originating in China PR was under challenge before the WTO DSB. Clearly, the issue regarding China's status as a market economy country was not before the WTO Appellate Body.

- b. China's accession protocol does not provide that China will get market-economy status after fifteen years automatically. It just says that a very specific provision of para 15 (a)(ii) will cease to apply. The other parts of Article 15 (including Article 15(a)(i)) continue to apply. Article 15(a) clearly provides that the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices. Article 15(a)(i) further provides that Chinese prices or costs shall be used if the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail.
 - c. Annexure 1, Rule 8(4) of the Anti-dumping Rules, 1995 clearly provides that the Designated Authority (DA) may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of criteria, has been treated as a market economy country for the purpose of anti-dumping investigations, by a WTO member country. There is no evidence provided by the interested parties to satisfy this criteria for China PR.
 - d. The date of initiation of present investigation was June 29, 2016. The date of expiry contemplated in China PR's accession protocol is December 11, 2016. Even if the expiration of provision has the stated effect as alleged by the interested parties, the same cannot be applied with retrospective effect so as to apply to investigations that were initiated prior to December 11, 2016.
 - e. None of the Chinese producers can satisfy market economy status.
 - f. Unless the responding Chinese exporters conform to the standards laid down under the Rules, the Designated Authority is required to determine the normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.
 - g. None of the producers/exporters from China PR has claimed market economy treatment.
28. The domestic industry has made detailed submissions requesting that the producers/exporters treated as non-cooperating should be continued to be treated as non-cooperating in the final findings as well.

G.4. Examination by the Authority

Market Economy claims for Chinese producers

29. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

- (a) *In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*
 - (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
 - (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take*

into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

30. Article 15 implies that provisions of one of the subparagraph shall expire 15 years from date of China's Accession. The provisions of this paragraph expired on 11th Dec., 2016. Since the factum of dumping causing injury to the domestic industry is established based on investigation period, the conditions prevalent during the investigation period alone is relevant, appropriate and necessary for the purpose of present investigation. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation is July 2015 to December 2015. Since the sub-paragraph of Article 15 was in existence during the period of investigation, the Authority may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.
31. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the Rules.
32. As per Paragraph 8, Annexure I to the AD Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 to prove market economy status. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in subparagraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether:
 - a. The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values.
 - b. The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts.
 - c. Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms.
 - d. The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
33. It is noted that none of producers of subject goods in China PR have claimed market economy treatment. Accordingly, the authority is not required to examine any of the above criteria for Chinese Producers and holds that producers/exporters from China PR are not operating under market economy conditions and therefore, has adopted the constructed normal value for determination on normal value in terms of Para-7 to Annexure-1 to the Rules.

G.5. Determination of Normal Value

34. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed. The following parties have filed exporter questionnaire responses:
- i. Shandong Hwafone Steel Co. Ltd, China PR (Producer)
 - ii. Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd, China PR (Exporter)
 - iii. Zhnagjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd, China PR (Producer)
 - iv. Shagang International Singapore Pte Ltd, China PR (Exporter)
 - v. Qingdao RHT Steel Co. Ltd, China PR (Exporter)
 - vi. Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co. Ltd, China PR (Producer/Exporter)

Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR

35. It is noted that none of the producers of subject goods in China PR have claimed market economy treatment. Therefore, the Authority has adopted the constructed normal value for determination of the normal value in terms of Para-7 to Annexure-1 to the Rules.
36. In view of the above, the normal value for China PR is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. As per the provisions of Para 7 of Annexure I, the normal value in China PR is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country, or the constructed value in a market economy third country, or the export prices from such a third country to any other country, including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include reasonable profit margin.
37. In the absence of any reliable price and cost details for the subject goods in any market economy third country, the Designated Authority has constructed the normal value for China PR on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the Normal Value for all the producer/exporters of the subject goods from China PR has been constructed and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Determination of Normal Value for producers and exporters in European Union

38. The Authority notes that no producer/exporter from the European Union has responded to and cooperated with the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in the EU, the Authority has determined weighted average normal value at ex-factory level for subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

G.6. EXPORT PRICE

M/s Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd, China PR (Producer) through related traders M/s Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd, China PR and M/s Shagang International (Singapore) Pte. Ltd, Singapore

39. From the response filed by M/s Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd, China PR ("Shajing"), the Authority notes that Shajing is the producer of the subject goods. Its related company, M/s Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd ("Shagang International") has exported the subject goods to India through another related trading company M/s Shagang International (Singapore) Pte. Ltd. ("Shagang SG").
40. From the response submitted by Shagang SG, the Authority notes that Shagang SG has further resold the subject goods to Samsung C and T Corporation, Korea ("Samsung"). Samsung has not filed any response. Further, Shajing has not reported any exports to India in Appendix-2. In the absence of information in Appendix-2 from the producer, it is not possible to ascertain the ex-factory export price to India.

41. Therefore, in view of absence of complete information from Shajing including non-cooperation by Samsung, the Authority does not accept the response filed by Shajing. Accordingly, the export price for Shajing is based on the facts available with the Authority.

Shandong Hwafone Steel Sheet Co., Ltd. (Producer) through unrelated trader M/s. Qingdao RHT Steel Co., LTD.

42. From the response filed by M/s Shandong Hwafone Steel Sheet Co., Ltd, China PR ("Hwafone"), the Authority notes that Hwafone is the producer of the subject goods and has exported the subject goods through unrelated trader M/s Qingdao RHT Steel Co., Ltd ("RHT"). Hwafone has reported all the sales as domestic sales in the appendices filed by it. It has not reported any exports to India in Appendix-2 even though in the questionnaire response filed by Hwafone, it has expressly stated that it has exported the goods to India through RHT. The authority also notes that there is a mismatch in the information submitted by Hwafone and RHT.
43. Therefore, in view of the above, the Authority does not accept the response filed by Hwafone. Accordingly, the export price for Hwafone is based on the facts available with the Authority.

M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd (Producer/Exporter)

44. From the response filed by M/s Jiangyin Xingcheng Special Steel Works, Co., Ltd, China PR ("JXSS"), the Authority notes that JXSS has exported plates having thickness more than 6mm and same are not covered under the scope of the PUC. Therefore, no examination is done for information submitted by JXSS.

Export Price for non-cooperating producers and exporters from China PR

45. The Authority notes that no other producer/exporter from China PR has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in China PR, including the above mentioned producers/exporters whose responses have not been accepted by the Authority, the Authority has determined the weighted average export price for subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

Export Price for producers and exporters in European Union

46. The Authority notes that no producer/exporter from EU has responded to the Authority in the present investigation. For all the non-cooperative producers/exporters in EU, the Authority has determined the weighted average export price as for subject goods on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

G.7. DUMPING MARGIN

47. The export price to India (net of all the adjustments claimed by the exporter and accepted by the Authority) has been compared with the normal value to determine the dumping margin. The dumping margin during the POI for all the exporters/producers from the subject countries has been determined as shown in the Dumping Margin Table below.

Dumping Margin Table

S. No	Country	Producer	Exporter	Normal Value USD	Net Export Price USD	Dumping Margin USD	Dumping Margin %	Dumping Margin Range %
1.	China PR	All	All	***	***	***	***	50-60
2.	European Union	All	All	***	***	***	***	70-80

48. It is seen that the dumping margins are quite significant and more than the de-minimis limits prescribed under the Rules in respect of the exports made by all the producers-exporters of the product under consideration from the subject countries.

H. Determination of Injury and Causal Link

49. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into

account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

H.1. Views of Exporter, importers and other Interested Parties regarding the injury claims of domestic industry

50. The submissions made by the opposing interested parties with regard to injury related issues and considered relevant by the authority are as follows:

- a. The Petition does not contain adequate and sufficient evidence of dumping and injury.
- b. The performance of the domestic industry has been stable and has improved. There is no change in the landed value, price undercutting has declined, production of the domestic industry and capacity utilization has increased.
- c. The injury is caused by the adverse export performance of the domestic industry. The injury has been caused by factors other than imports from China PR.
- d. The demand for retroactive measures is unwarranted.
- e. The cumulation is not appropriate in the light of the conditions of competition given that the Chinese imports account for 84% of the total imports.
- f. The domestic industry does not suffer injury given that most of the economic parameters either show a positive trend or are largely stable. The production, demand, sales, capacity and capacity utilization have increased.
- g. The domestic industry is loss making but it was already loss making in 2012-13 at the beginning of the period considered for the injury determination.
- h. The injury has been caused by other factors that the authority is required to examine.
- i. The domestic industry has not been making profit since the beginning of the period considered for the injury determination. Petitioners were already making losses in 2012-13.
- j. Performance of the domestic industry which has a problem of efficiency with utilization rate fluctuating around 50%. The decision to invest and increase the production capacity has caused the injury.
- k. The imposition of Anti-Dumping Measures will trigger price increase, which is not in public interest.

H.2. Views of the domestic industry

51. The following are the submissions with regard to injury related issues made by the domestic industry and considered relevant by the Authority:

- a. Imports of the subject goods have increased in absolute terms over the entire period of investigation. Imports of the PUC from the subject countries have increased in absolute terms.
- b. Imports of the subject goods have increased relative to production and also relative to consumption in India.
- c. Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand and the market share of imports from subject countries sharply increased from 2012-13 to POI (A).
- d. The Domestic Industry has not been able to increase its production and sales commensurate with the increase in demand.

- e. Inventories of the Domestic Industry have been on the rise as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
- f. There is significant price depression and suppression due to low priced dumped imports coming into India.
- g. The Domestic Industry's profitability has been drastically affected. The profitability has followed a negative trend during the entire injury period and the losses have further aggravated during the POI.
- h. The export performance of the Domestic Industry in no way has affected its financial and economic situation. Also, the petitioners have ignored the information related to exports while examining the injury parameters and entire injury analysis is based only on domestic performance of Applicants.
- i. The analysis overwhelmingly indicates that the Domestic Industry is suffering material injury due to increasing dumped imports of PUC into India. There exists a strong nexus between the increase in dumped imports of the subject goods and the material injury being suffered by the Domestic Industry.
- j. Interested parties have submitted that injury being suffered by the domestic industry is due to other factor and over capacities. These claims are very general and without any facts and figures to support. The fact that injury has been caused due to dumped imports of the subject goods in India has already been established. The domestic industry has been in existence since many years and has been doing well in the past.

H.3. Examination of the issues by the Authority

52. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under:
- a. The Authority notes that landed value of imports of the subject goods from the subject countries has declined and the domestic industry has been forced to match such low prices causing material injury to domestic industry.
 - b. With regard to the export performance of the domestic industry, the authority notes that the entire injury analysis is based only on the domestic performance of the DI.
 - c. The Authority has further analysed the contention of the interested parties that injury being suffered by the domestic industry is due to other factors. These claims are without any supporting facts and figures.

Cumulative Assessment

53. Article 3.3 of WTO agreement and Annexure II para (iii) of the Anti-dumping Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article, and
 - b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.
54. The Authority notes that:
- a. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margins of dumping from each of the subject countries are more than the de minimis limits prescribed under the Rules.

- b. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- c. Cumulative assessment of the effects of imports is appropriate as the exports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.
55. In view of the above, the Authority considers that it would be appropriate to assess injury to the domestic industry cumulatively from exports of the subject goods from the subject countries.
56. Rule 11 of AD Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the AD Rules.

Volume Effect of Dumped Imports and Impact on Domestic Industry

Assessment of Demand

57. The demand of subject goods has been determined by adding the domestic sales of Indian producers of like product with the imports of the subject goods from all countries. For the purpose of present injury analysis, the Authority has relied on the import data procured from DGCI&S. The Authority notes that demand of subject goods increased over the injury period as can be seen in the table below:

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Total dumped imports from subject countries	60,771	73,854	2,09,895	4,12,322	2,13,311	4,26,622
Imports from other countries	41	304	0	192	0	0
Total imports	60,812	74,159	2,09,895	4,12,513	2,13,311	4,26,622
Domestic sales of petitioners	2,30,213	3,27,096	3,08,076	4,15,032	1,89,723	3,79,446
Domestic sale of other producers	2,25,874	1,71,790	1,92,146	2,25,007	1,09,928	2,19,857
Total Demand/Apparent consumption	5,16,898	5,73,045	7,10,117	10,52,552	5,12,963	10,25,925

Import Volumes and Share of Subject countries

58. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject good from the subject countries has been analyzed as under:

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Dumped imports from subject countries	60,771	73,854	209,895	412,322	213,311	426,622
Trend	100	122	345	678	351	702
Imports from other countries	41	304	0	192	0	0

Particulars (in MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Trend	100	748	-	471	-	-
Total Imports	60,812	74,159	209,895	412,513	213,311	426,622
Trend	100	122	345	678	351	702
Total Demand/Apparent consumption	5,16,898	5,73,045	7,10,117	10,52,552	5,12,963	10,25,925
Trend	100	111	137	204	99	198
Dumped imports from Subject Countries relative to consumption	12%	13%	30%	39%	42%	42%
Production of Petitioners	4,14,910	5,76,975	5,59,218	5,91,385	2,77,318	5,54,636
Dumped imports from Subject Countries relative to petitioners' total production	15%	13%	38%	70%	77%	77%

59. The Authority notes as under from the above table:

- Imports of subject goods from subject countries have increased in absolute terms from 60,771 MT in 2012-13 to 426,622 MT in POI (A).
 - Imports of subject goods from subject countries have increased in relation to petitioners' production from 15 % in 2012-13 to 77 % in POI (A).
 - Imports of the subject goods from the subject countries have increased in relation to consumption in India from 12% in 2012-13 to 42% in POI (A).
60. It is, thus, concluded that imports of the PUC from the subject countries have increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India.

Price Effect of the Dumped Imports on the Domestic Industry

61. With regard to the effect of the dumped imports on prices, Annexure II (ii) of the Rules lays down as follows:

"With regard to the effect of the dumped imports on prices as referred to in sub-rule (2) of rule 18 the Designated Authority shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred to a significant degree."

62. It has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of dumped imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

Price Undercutting

63. In order to determine whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, the Authority has compared landed price of imports with net sales realization of the domestic industry. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level. The domestic prices and margin of undercutting is shown as per the table below:

Price Undercutting	July 15 to Dec 15	China PR	EU
Landed Value	Rs. /MT	40,761	35,801
Domestic Selling Price	Rs. /MT	***	***
Price Undercutting	Rs. /MT	***	***
Price Undercutting	% of LV	***	***
Price Undercutting Range		20-30%	35-45%

64. The authority notes from the aforesaid table that significant price undercutting exists for China PR as well as European Union.

Price Suppression/Depression

65. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars (Rs. per MT)	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015	POI (July 2015- Dec 15)
Cost to make and sell	***	***	***	***	***
Trend	100	104	106	95	94
Domestic Selling Price	***	***	***	***	***
Trend	100	104	105	93	91
Landed Value	41,440	45,340	45,338	41,501	40,372
Trend	100	109	109	100	97

66. It is noted that decline in the domestic selling price is higher than the decline in the cost of sales. The import prices have remained significantly lower than the domestic selling prices as well as the cost to make and sell for domestic industry throughout the injury investigation period. The low priced dumped imports did not allow the domestic industry to fetch a selling price which could recover even its cost. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry in the market.

Economic parameters of the domestic industry

67. Annexure II to the Anti-dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. An examination of performance of the domestic industry reveals that the domestic industry has suffered material injury. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

68. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity & capacity utilization was as follows:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 15)	POI (A)
Installed Capacity (MT)	7,15,000	10,73,000	10,83,000	10,83,000	5,41,500	10,83,000
Total production (MT)	4,14,910	5,76,975	5,59,218	5,91,385	2,77,318	5,54,636
Capacity Utilization	58%	54%	52%	55%	51%	51%
Domestic Sales	2,30,213	3,27,096	3,08,076	4,15,032	1,89,723	3,79,446

69. The Authority notes that even though the domestic production of the subject goods have increased, the significant increase in dumped imports has not allowed the domestic industry to achieve optimum capacity utilisation during injury investigation period.

Profitability

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015- Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 2015)	POI (A)
Profit Before Tax (PBT) (Rs. In crores)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	(100)	(150)	(166)	(253)	(127)	(254)
PBT (Rs./MT)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	(100)	(106)	(124)	(140)	(153)	(153)
Cash Profits (PBT+Depreciation) (Rs. crores)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	(100)	(133)	(174)	(282)	(144)	(287)
Cash Profit (Rs./MT)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	(100)	(94)	(130)	(156)	(174)	(174)

70. The Authority notes the following from the above table:

- The domestic industry's profitability has been adversely affected due to increased dumping by exporters from subject countries. The losses suffered by the domestic industry have significantly increased during POI.
- Due to severe dumping from subject countries during POI, domestic industry has not been able to recover its cost of sales leave aside earning a reasonable profit.

Return on capital employed

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI (A)
ROCE%	***	(***)	(***)	***
Trend	100	(471)	(802)	111

71. The authority notes that the domestic industry has not been able to earn an adequate return on capital employed throughout the injury investigation period. Due to severe dumping from subject countries during POI, domestic industry has not been able fetch a selling price which can provide for a reasonable return on capital employed.

Market Share

72. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below:

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	April 2015-Dec 2015 (A)	POI (Jul 2015- Dec 2015)	POI (A)
Demand (MT)	5,16,898	5,73,045	7,10,117	10,52,552	5,12,963	10,25,925
Indexed	100	111	137	204	99	198
Market Share						
Share of Petitioners	45%	57%	43%	39%	37%	37%
Share of all other Producers	44%	30%	27%	21%	21%	21%
Share of Subject countries	12%	13%	30%	39%	42%	42%
Share of Other countries	0%	0%	0%	0%	0%	0%

73. From above table, the Authority observes that the market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. Further, the authority notes that market share of the imports from the subject countries has increased over the injury period. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
74. The domestic industry has not been able to increase the sales of the PUC commensurate with the increase in demand because of the significant volume of dumped imports coming from the subject countries.

Inventories

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Jul 2015- Dec 15)
Average Inventory (MT)	27,044	36,707	38,220	61,980
Trend (Indexed)	100	136	141	229

75. The Authority notes that the Domestic Industry is facing significant accumulated inventories. The levels of inventories have been increasing as compared to the base year. Due to increasing imports, the market share of the Domestic Industry has come down and the increased demand has been significantly captured by imports. As a result, the Domestic Industry is unable to increase its production and sales which is leading to a situation of inventory accumulation over the injury period.

Productivity of the domestic industry

76. The Authority notes that deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry. It can be seen in the table given below that productivity has increased from 100 indexed points in 2012-13 to 145 indexed points during the POI.

Particulars	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity	***	***	***	***
Trend	100	139	134	145

Growth

Particulars	Unit	2013-14	2014-15	POI(A)
Cost of Production	%	4%	2%	-11%
Selling Price	%	4%	1%	-13%
Loss	%	50%	11%	53%
Cash Loss	%	33%	31%	65%
Market Share	%	12%	-24%	-15%

77. The Authority notes that the growth of the domestic industry with regard to profitability, market share and selling price has been negative.

Ability to raise capital investments

78. The Authority notes that given the rising demand of the product in the country, the domestic industry has made investments in plant and machinery. However, despite these investments, the performance of the domestic industry has deteriorated considerably and further investments may get adversely affected.

Level of dumping & dumping margin

79. It is noted that imports from the subject countries are entering into the country at dumped prices and that the margins of dumping are significant.

Factors Affecting Domestic Prices

80. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc., shows that the landed value of imported material from the subject countries is below the selling price as well as the non-injurious price of the domestic industry, causing significant price under-cutting and price under-selling in the Indian market. Thus, the primary factor affecting the domestic prices is landed value of subject goods from the subject countries.
81. It is thus seen that there has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms. The imports have increased significantly in relation to consumption and production of the product in India. Imports have thus increased both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Dumped imports have had significant adverse price effect in terms of price suppression, price depression and price under-cutting. Effect of dumped imports has been to reduce the domestic prices of the subject goods. Low priced dumped imports have forced the domestic industry to fetch a market price which could not even cover its cost. The domestic industry is facing price underselling. There does exist significant price depression and suppression due to low priced dumped imports coming in India. The dumping margin determined by the Authority is quite significant. The Domestic Industry's profitability and return on capital employed have been affected during POI.

I. Causal Link

82. The Authority has examined whether other factors listed under the Anti-dumping Rules could have contributed to injury to the domestic industry. The examination of causal link between dumping and material injury to the domestic industry has been done as follows:

Imports from third countries

83. The imports from countries other than subject countries are not significant in volume terms so as to cause or threaten to cause injury to the domestic industry. Moreover, the price at which goods are coming from other countries is much higher than the price at which goods are coming from subject countries.

Contraction in demand

84. The demand for the subject goods has shown an increasing trend. Accordingly, fall in demand cannot be the reason for injury to the domestic industry. In fact, the domestic industry has not been able to increase its sale and market share commensurate to increase in demand.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

85. The Authority notes that there is no trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.

Developments in technology

86. The technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor of causing injury to the domestic injury.

Changes in pattern of consumption

87. The domestic industry is producing the type of goods that have been imported into India. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

Export performance

88. Claimed injury to the domestic industry is not on account of possible significant deterioration in export performance of the domestic industry. In fact, exports by the domestic industry have not materially declined. In any case, the Authority has considered domestic performance wherever possible.

Performance of the domestic industry with respect to other products

89. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

Productivity of the domestic industry

90. The Authority notes that deterioration in productivity has not caused injury to the domestic industry.

Factors establishing causal link

91. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated due to dumped imports from the subject countries. Causal link between the dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- Imports of the subject goods from the subject countries have increased in absolute terms over the entire period of investigation.
 - Imports of the subject goods from the subject countries have increased relative to production and consumption in India.
 - Market share of the Domestic Industry has decreased even though demand for the subject goods has been rising in India. This is due to the reason that imports have aggressively captured the increase in demand.
 - Inventories of the Domestic Industry have been on the rise as the Domestic Industry has not been able to increase its sales despite increase in demand. Imports have been aggressively capturing the demand in India.
 - There exists price suppression and price depression due to low priced dumped imports coming in to India.
 - The Domestic Industry's profitability has been drastically affected. This is evident from the fact that the losses suffered by the domestic industry have significantly increased during the POI.

J. Conclusion on Injury and Causation

92. From the above examination of injury and causal link, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumping of the subject goods from the subject countries. There has been a significant increase in the volume of dumped imports from the subject countries in absolute terms throughout the injury period and in relation to production and consumption in India. The dumped imports have had significant adverse effect on the prices of the domestic industry in the market. The dumping margin for the subject countries has been determined and is considered significant. Dumped imports from the subject countries have adversely impacted capacity utilization of the domestic industry. Market share of the subject imports has significantly increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profits, cash profits and return on investments. The Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury as a result of dumped imports from the subject countries.
93. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry and compared it with the landed values of the subject imports from the subject countries to determine the injury margin. The injury margins have been determined as follows:

Injury Margin

S.No	Countries	Producer	Exporter	NIP USD	Landed Value USD	Injury Margin USD	Injury Margin %	Injury Margin Range %
1.	China PR	All	All	***	***	***	***	30-40
2.	EU	All	All	***	***	***	***	45-55

94. The level of dumping margins and injury margins as determined are significant.

K. Post Disclosure Statement submissions by the Interested Parties

95. The post disclosure submissions have been received from various interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

Submissions made by the Domestic Industry

96. The following submissions have been made by the domestic industry:
- a. The non-injurious price computed in the subject investigation seems to be understated. In particular, the NIP computed for JSW Steel Coated Products Limited (“JSCPL”) and Essar Steel India Limited (“Essar”) is understated.
 - b. From the confidential NIP workings shared by the Designated Authority, the domestic industry understands that NIP for JSCPL has been computed by considering the transfer price (being the market price) for HR Coils as input cost for the subject goods manufactured by JSCPL. The transfer price for HR Coils was very low during the POI because of dumped imports of HR Coils coming into India. The transfer price so considered does not even cover the cost of production of HR Coils, leave aside reasonable return, thereby keeping the NIP for JSCPL low. The authority is, therefore, requested to consider the full cost as well as the return on the capital employed for manufacturing HR Coils used by JSCPL as inputs for manufacturing the subject goods.
 - c. From the confidential NIP workings shared by the Designated Authority, it is understood that certain deductions have been made from the net fixed assets while calculating the return on capital employed for Essar. Further, it was submitted that:
 - i. The Designated Authority should consider all the assets for Essar as reflected in the audited books of accounts.
 - ii. All the amounts have been capitalized in the books of accounts as per the relevant Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. There is no reason for the Designated Authority to go beyond the audited books of accounts and disallow any amount on arbitrary basis. There is no provision in the law that allows the Designated Authority to make any such deduction from the assets deployed by the domestic industry.
 - iii. It was also submitted that the deductions made by the Designated Authority are contrary to Annexure III to the AD Rules. The Designated Authority’s approach is arbitrary and in violation of principles of natural justice. The above issues should be immediately addressed and all the net fixed assets should be considered in computing the NIP.
 - d. It has been submitted by the domestic industry that the reference price based duty has not been able to put adequate checks on the quantum of imports of the subject goods into India. The imports from the subject countries have been significant even after imposition of provisional anti-dumping duty. In addition, it has also been noticed that the import prices have been hovering around the reference price fixed by the authority in the provisional findings despite there being a significant increase in the input costs after the POI. The domestic industry has requested the authority to recommend fixed duty in the final findings to give appropriate protection to the domestic industry. Application of fixed form of duty will ensure the effectiveness of measures as it would reduce the likelihood of price manipulation or circumvention.
 - e. Level of anti-dumping duties imposed by other countries like US and the European Union are very high on imports of colour-coated steel products in light of the severe dumping and injury faced by their respective domestic industries.

Submissions made by other interested parties

97. The submissions made by the other interested parties have been summarized as below:
- a) It is submitted that no examination of the data submitted by Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd., China PR (Producer) should be made as it has exported plates having thickness more than 6MM and same are not covered under the scope of Product Under Investigation.

- b) Separate assessment for Dumping Margin for Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd., is not appropriate.

Examination by the Authority

98. The Authority notes that most of the submissions made by interested parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above ipso facto deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined the submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:
- In response to the Disclosure Statement, M/s Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co. Ltd., China PR (Producer) and its trader's M/s Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd., China PR and M/s Shaganag International (Singapore) Pte. Ltd., Singapore, have informed that they have exported heavy plates of more than 6mm thickness to India which is not covered within the scope of PUC. The authority notes that since the product exported by these interested parties is not covered within the scope of PUC, their concern has already been addressed by the authority.
 - As regards the domestic industry's concerns regarding non-injurious price, the Authority observes that non-injurious price has been calculated in accordance with Annexure III of the AD Rules.
 - With regard to the request of domestic industry to recommend anti-dumping duty in the form of fixed duty rather than reference price, authority notes that reference price based form of duty is appropriate for subject goods keeping in mind the facts and circumstances of the case.

L. Indian industry's interest & other issues

99. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
100. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these product. The domestic industry submitted that imposition of proposed duty shall have insignificant cost implications for the consumer. Therefore, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M. Recommendations

101. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from the subject countries below normal value.
 - The domestic industry has suffered material injury on account of subject imports from the subject countries.
 - The injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject countries.
102. The Authority notes that the investigation was initiated and it was notified to all interested parties. Adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted an investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the Anti-Dumping Rules and having established a positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of definitive anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
103. Having regard to the lesser duty rule, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties

on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as the difference between the landed value of the subject goods and the amount indicated in Col 8 of the duty table appended below, provided the landed value is less than the value indicated in Col 8. The landed value of imports for this purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975. The validity of the recommended definitive anti-dumping duty, if accepted by the Central Government, will be upto a period of five years from the date of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No. 02/2017-Customs (ADD) dated 11.01.2017.

DUTY TABLE

S.No.	Heading/ Sub heading	Description of Goods*	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	7210, 7212, 7225 and 7226	Pre-painted, painted, colour coated or organic coated flat steels in coils or not in coils whether or not with metallic coated substrate of zinc, aluminium- zinc or any other substrate coating	China PR	China PR	Any	Any	822	MT	US\$
2.	- do -	- do -	China PR	Any country other than the subject countries	Any	Any	822	MT	US\$
3.	- do -	- do -	Any country other than the subject countries	China PR	Any	Any	822	MT	US\$
4.	-do-	-do-	European Union	European Union	Any	Any	822	MT	US\$
5.	-do-	-do-	European Union	Any country other than the subject countries	Any	Any	822	MT	US\$
6.	-do-	-do-	Any country other than the subject countries	European Union	Any	Any	822	MT	US\$

***Note: The description of goods does not include the plates of thickness of 6mm or more.**

104. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

Dr. INDER JIT SINGH, Designated Authority.